



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

क्रमांक 27
दृष्टि 50क्रमांक 27
दृष्टि 50
क्रमांक 27
दृष्टि 50

सं. 108]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 26, 2010/वैशाख 6, 1932

पुरा

No. 108]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 26, 2010/VAISAKHA 6, 1932

पुरा

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

प्रभारी
राज्य विभाग एकान्त

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2010

विषय : यूरोपीय संघ के मूल के अधिकार वहां से निर्यातित पीवीसी पेस्ट रेजिन के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच—अंतिम जांच परिणाम ।

सं. 15/27/2008-डीजीएडी—यतः समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय संघ (जिसे आगे संबद्ध देश/क्षेत्र कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित पीवीसी पेस्ट रेजिन (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर 7 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना सं. 104/2004-सी.शु. के तहत मूलतः निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

ख. पृष्ठभूमि

2. और यतः इंडियान मैटल एंड फैरो एलॉयज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी की रिट याचिका (सिविल) सं. 2006 की 16893 के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9(5) के अनुसार प्राधिकारी ने लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, के लिए निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हुए 31 मार्च, 2009 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया ।

3. और यतः 7 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना सं. 104/2004, दिनांक 7 अक्टूबर, 2004 के तहत अधिसूचित पाटनरोधी शुल्क की अवधि अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अनुसार 6 अक्टूबर, 2009 की सी.शु. अधिसूचना सं. 115/2009 के तहत 6 जुलाई, 2010 तक बढ़ाई गई थी ।

ग. प्रक्रिया

4. इस कार्यवाही में नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है :

i. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार भारत स्थित यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के कार्यालय को जांच की शुरुआत के बारे में सूचित किया गया था ।

ii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 31 मार्च, 2009 की जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां भारत स्थित यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के कार्यालय, उसके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग को भेजी। इस जांच से संबंधित पक्षकारों से प्रश्नावली का उत्तर दायर करने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था। निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावलियों की प्रतियां इस अनुरोध के साथ ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची के साथ भारत स्थित यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल के कार्यालय को भी भेजी गई थी कि वे निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें।

iii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मांगने के लिए संबद्ध क्षेत्र के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं :

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1.	वेस्टोलिट जीएमबीएच एंड के. केजी, डेनमार्क
2.	ईवीसी बिजनेस सेंटर, यू.के.
3.	वेस्टोलिट जीएमबीएच एंड के. केजी, पोर्टफ्रेच, जर्मनी
4.	सोल्युशन एसए, ब्रूसेल्स, बेल्जियम
5.	विनोलिट, इस्लामिक, जर्मनी
6.	अल्कोनेल, बर्सेलोना

उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध क्षेत्र के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावलियों का उत्तर नहीं दिया।

iv. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना हेतु भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों, प्रयोक्ताओं और एसोसिएशनों को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:

क्र. सं.	कंपनी का नाम
1.	अकजो नोबल कोटिंग्स इंडिया प्रा.लि., कर्नाटक
2.	एलपी के.लि., केरल
3.	अनाबॉण्ड एक्सेस इंडिया प्रा.लि., चेन्नई
4.	क्रिएटिव वर्ल्ड, मुंबई
5.	डी सी मिल्स (प्रा.) लि., केरल
6.	डीआरजी लेदर प्रा.लि., केरल
7.	एफटेक शॉर्फ इंडिया लि., मुंबई
8.	फेनर कचेयर बेल्टिंग प्रा.लि., तमिलनाडु

9.	फेनोप्लास्ट लि., आंध्र प्रदेश
10.	हालोल लेदर क्लॉथ लि., मुंबई
11.	हैंकल टेरोसन इंडिया (प्रा.) लि., हरियाणा
12.	हिंदुस्तान सीयल्स लि., कोलकाता
13.	इंटरनेशनल कन्वेयर लि., औरंगाबाद
14.	जैश इंडस्ट्रीज लि., नई दिल्ली
15.	केराफाइबर टेक्स इंटरनेशनल प्रा.लि., कोचीन
16.	केरल बॉलर्स लि., केरल
17.	मयूर यूनिकोट्स लि., जयपुर
18.	ओस्याल बेबल्स प्रॉडक्ट्स, नई दिल्ली
19.	फिरोज सेथना प्रा.लि., मुंबई
20.	पोलमानन इंडिया लि., मुंबई
21.	पॉलीनोवा इंडस्ट्रीज लि., गोआ
22.	प्रीमियर पोलीफर्म लि., नई दिल्ली
23.	रोटो स्क्रीनटेक लि., राजकोट
24.	शिवम टेक्सटाइल्स, नई दिल्ली
25.	सियल तिजिट लि., कोलकाता
26.	स्नेह विनायत प्रॉडक्ट्स प्रा.लि., आंध्र प्रदेश
27.	एसआरएफ लिमिटेड, तमिलनाडु
28.	टेक्सोन इंडस्ट्रीज प्रा.लि., चेन्नई

क्र. सं.	एसोसिएशन का नाम
1.	लेदर क्लॉथ एंड प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एलसीपीएमए), नई दिल्ली

उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में मै. मयूर यूनिकोट्स लि. तथा मै. जैश इंड लि. ने आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए; जबकि संबद्ध वस्तु के आयातकों एवं प्रयोक्ताओं की एक एसोसिएशन लैदर क्लॉथ एंड प्लास्टिक्स मैन्यु. एसो. (एलसीपीएमए) ने इस विषय में अपने अनुरोध दायर किए।

- v. जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में मै. कैम प्लास्ट लि., चेन्नई ने उत्तर दिया और निर्णायक समीक्षा करने का अनुरोध करते हुए सूचना/आंकड़ों के साथ अपने अनुरोध प्रस्तुत किए तथा अन्य बातों के साथ-साथ पाटनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ाने की मांग की। कंपनी ने क्षति विश्लेषण हेतु सूचना/आंकड़े प्रस्तुत किए। तथापि, मै. फिनोलैक्स इंड लि. ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया।
- vi. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से जांच अवधि और पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए आयात के आंकड़े मांगे गए थे।
- vii. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों तथा साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा जिसे हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षणार्थ खुला रखा।

viii. प्राधिकारी ने मै. कैमप्लास्ट सनमार लि., चेन्नई द्वारा प्रस्तुत सूचना की संभव सीमा तक जांच सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएपी) के आधार पर की ताकि हुई क्षति का विश्लेषण किया जा सके और भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत, उसे बनाने और बेचने की लागत निकाली जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ।

ix. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 25 फरवरी, 2010 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर भी प्रदान किया । जिन पक्षकारों ने सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त किए थे, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का आग्रह किया गया था । हितबद्ध पक्षकारों से लिखित अनुरोधों/प्रत्युत्तरों में किए गए तर्कों पर इस जांच परिणाम में जहां संगत पाया गया है, विचार किया गया है ।

x. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि अप्रैल, 2008-मार्च, 2009 (जांच अवधि) है । तथापि, क्षति विश्लेषण में अप्रैल, 2005-मार्च, 2006, अप्रैल, 2006-मार्च, 2007, अप्रैल, 2007-मार्च, 2008 की अवधि और जांच अवधि शामिल है ।

xi. पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा विचारित आवश्यक तथ्यों का प्रकटन ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को किया गया था । प्रकटन विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों पर इस जांच परिणाम में विधिवत विचार किया गया है ।

xii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी । संतुष्ट होने के बाद प्राधिकारी ने अपेक्षानुसार गोपनीयता के दावे स्वीकार किए हैं और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है । जहां कहीं संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था ।

xiii. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर ये जांच परिणाम दर्ज किए हैं ।

xiv. *** यह चिन्ह इस अधिसूचना में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का दोतक है और प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है ।

घ. प्रकटन विवरण के उत्तर में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

5. निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन विवरण का उत्तर दिया है:

1. मै. कैमप्लास्ट सनमार लि., चेन्नई
2. मै. मयूर यूनीकोटर्स लिमिटेड, जयपुर; तथा
3. मै. लोदर क्लॉथ एंड प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली

6. मै. कैमप्लास्ट सनमार लि. द्वारा किए गए अनुरोध

- घरेलू उद्योग ने अपने पूर्ववर्ती अनुरोध दोहराए हैं और यह तर्क दिया है कि सर्वेंशन तथा पेस्ट पीवीसी ने अंतर के संबंध में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को अस्वीकार किया जाना चाहिए ।
- घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पीवीसी पेस्ट रेजिन का उपयोग टाप कोड तथा फॉम कोड दोनों में किया जाता है । कंपनी द्वारा पीवीसी पेस्ट रेजिन के तीन ग्रेडों 120, 121 तथा 124 का उत्पादन किया जाता है । चर्म वस्त्र में 3 परतें होती हैं और सभी तीनों परतों को याचिकाकर्ता के उत्पाद के 124 ग्रेड से तैयार किया जा सकता है । ग्रेड 120 का उपयोग सीलेंट आदि के उत्पादन में किया जाता है और 121 का उपयोग वहां किया जाता है जहां उच्च क्षमता की जरूरत होती है अर्थात् फुटबॉल आदि के उत्पादन में प्रयुक्त किए जाने वाले चर्म वस्त्र के लिए । अतः विरोधी पक्षकारों का दावा गलत है । संक्षेप में घरेलू उद्योग ने टॉप कोड तथा फॉम कोड के बारे में अपने तर्कों को दोहराया है और यह अनुरोध किया है कि इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों का दावा आधारहीन है ।
- जहां तक घरेलू उद्योग के आधार का संबंध है, याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि भारतीय बाजार में इस उत्पाद के दो उत्पादक हैं और कंपनी का हिस्सा कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है और याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है ।

7. मै. मयूर यूनीकोटर्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा किए गए अनुरोध

- यह उल्लेख किया गया है कि उन्हें प्रकटन विवरण की प्रति समय पर प्राप्त नहीं हुई और वह मै. लैदर क्लॉथ एंड प्लास्टिक्स मैन्यु एसो. के पत्र के जरिए प्राप्त हुई और इसलिए उन्होंने समय बढ़ाने की मंशा व्यक्त की ।
- यह तर्क दिया गया है कि उन्हें और एसोसिएशन के सभी सदस्यों को मै. कैमप्लास्ट सनमार लि., चेन्नई द्वारा विनिर्मित तथा आपूर्त उत्पाद पीवीसी रेजिन (इमल्सन ग्रेड) नहीं है अपितु पीवीसी रेजिन है ।

8. प्राधिकारी द्वारा जांच

- प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण मै. मयूर यूनिकोटर्स लि., जयपुर सहित जांच में भाग लेने वाले समस्त हितबद्ध पक्षकारों को स्पीड पोस्ट द्वारा विधिवत भेजा गया था । अतः यह कहना सही नहीं है कि प्रकटन विवरण मै. मयूर यूनीकोटर्स लि. के पास नहीं भेजा गया था । प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि इस जांच को पूरा करने में समय की कमी के कारण इस अंतिम चरण पर किसी हितबद्ध पक्षकार को समय विस्तार प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है ।
- प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच की शुरूआत के समय पर ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस जांच का क्षेत्र और विस्तार पीवीसी पेस्ट रेजिन (इमल्सन ग्रेड) है । प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि किसी निर्णायक समीक्षा जांच में जांच के दायरे को बढ़ाया नहीं जा सकता ।

9. मै. लेदर क्लॉथ एंड प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली द्वारा किए गए अनुरोध

- यह तर्क दिया गया है कि पेस्ट रेजिन और सस्पेंशन रेजिन के बीच एकमात्र अंतर उनका पार्टीकल साइज है। अन्यथा वे अनुप्रयोग, विनिर्माण, कच्ची सामग्री की लागत तथा अंतिम उत्पादों के रूप में समान हैं। पीवीसी सस्पेंशन रेजिन रासायनिक रूप से पीवीसी पेस्ट रेजिन के समान है, केवल उसकी भौतिक दिखावट अलग होती है।
- जहां तक पेस्ट रेजिन के विभिन्न ग्रेडों की पारस्परिक तुलना का संबंध है, यह कहना सही नहीं है कि पेस्ट रेजिन के सभी ग्रेडों का आणविक भार, वायु निर्गम गुणधर्म और नैसर्जिक व्यवहार समान हैं। अलग-अलग ग्रेड अलग-अलग अनुप्रयोगों के लिए होते हैं और उनमें अंतर शून्य से लेकर 400 डॉलर तक होता है। उनसे अलग-अलग उत्पाद तैयार किए जाते हैं तथा उनका अलग-अलग अनुप्रयोग होता है भले ही वे सस्पेंशन ग्रेड रेजिन हो अथवा पेस्ट ग्रेड रेजिन।
- पीवीसी पेस्ट रेजिन के विनिर्माण में एकाधिकार बना हुआ है।
- वे उत्तम गुणवत्ता के पीवीसी पेस्ट रेजिन का आयात करते हैं और वे टॉप कोट की जरूरत हेतु पीवीसी पेस्ट रेजिन की प्रमुख गुणवत्ता के न्यूनतम 30% का आयात करने के लिए बाध्य हैं।
- ये आयात भारतीय खपत के केवल 6% हैं, अतः यह निष्कर्ष गलत है कि इस से हुए पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में भारी कटौती हो रही है।

10. प्राधिकारी द्वारा जांच

- जहां तक पेस्ट रेजिन और सस्पेंशन रेजिन के बीच अंतर का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस अनुरोध को दोहराने के अलावा एसोसिएशन ने अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। आगे यह नोट किया जाता है कि उन्होंने प्राधिकारी के समक्ष कारगर प्रस्तुतिकरण करने के लिए संगत आंकड़ों के संग्रहण हेतु लगभग 2 माह के समय विस्तार की मांग की है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह वर्तमान कार्यवाहियों में अत्यंत विलंबित अनुरोध है। प्राधिकारी के लिए पाटनरोधी नियमानुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करनी अपेक्षित होती है। एसोसिएशन द्वारा आज की तारीख तक अपने दावे की पुष्टि करते हुए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। तथापि, प्रकटन विवरण जारी होने के बाद नए तथ्यों को स्वीकार करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी अवसर प्रदान करना अपेक्षित हो सकता है। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस जांच को पूरा करने में समयाभाव के कारण किसी हितबद्ध पक्षकार को समय विस्तार देना व्यवहार्य नहीं है।
- जहां तक पेस्ट रेजिन के विभिन्न ग्रेडों की पारस्परिक तुलना से संबंधित अनुरोधों का प्रश्न है, एसोसिएशन द्वारा आज की तारीख तक अपने दावे की पुष्टि करते हुए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. कैमप्लास्ट सनमार लि. संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक नहीं है। इसके अलावा, प्रयोक्ताओं की आयातित उत्पाद की पहुंच भी हो सकती है परंतु यह पाटित कीमतों पर नहीं हो सकती है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क का

उद्देश्य आयातों को हतोत्साहित करना नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होती है ।

- एसोसिएशन ने गुणवत्ता के दावे की भी पुष्टि नहीं की है ।
- जहां तक इस मुद्दे का संबंध है, कि आयात भारतीय खपत के केवल 6% हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी पाटन तथा परिणामी क्षति की संभावना के निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं भले ही संबद्ध वस्तु का आयात जांच अवधि के दौरान न किया गया हो । ये आयात हर हालत में मात्रात्मक रूप में न्यूनतम स्तर से कुप्रीय अधिक हैं और इनसे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है जैसा कि क्षति विश्लेषण से नोट किया जा सकेगा ।

ड विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु

ड.१. मै. कैमप्लास्ट सनमार लि., चेन्नई द्वारा किए गए अनुरोध

11. मै. कैमप्लास्ट सनमार लि., चेन्नई ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- मूल जांच और वर्तमान समीक्षा में जांचाधीन उत्पाद पॉली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन है जिसे पॉलीविनायल क्लोराइड रेजिन (इमल्सन ग्रेड) अथवा पीवीसी पेस्ट रेजिन के नाम से भी जाना जाता है । इसका उत्पादन विनायल क्लोराइड मोनोमर (वीसीएम) से किया जाता है और वीसीएम का उत्पादन ई डी सी से होता है जिसके लिए प्रमुख कच्ची सामग्री के रूप में क्लोरीन की जरूरत होती है । इसका उत्पादन और बिक्री सफेद/मटमैले पाउडर के रूप में की जाती है । इसका उत्पादन कई ग्रेडों में किया जाता है जो "के मूल्य" में अलग-अलग होते हैं । विभिन्न ग्रेड तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है । इसका उपयोग कृत्रिम धर्म (रेक्सीन), कोटेड फैब्रिक, तिरपाल, कन्चेयर वेल्टिंग, खिलौनों, आटोमोटिव सीलेंट और आसंजकों आदि में किया जाता है ।
- यह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के उपशीर्ष सं. 39042210 के अंतर्गत वर्गीकृत है । यद्यपि आयातों की निकासी कई वर्गीकरणों में की गई है ।
- 39042110 के अंतर्गत वर्गीकृत पॉलीविनायल क्लोराइड (सस्पेंशन ग्रेड) संबद्ध वस्तु से भिन्न है और इसे विचाराधीन उत्पाद में शामिल नहीं किया गया है ।
- घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु आयातित उत्पाद की समान वस्तु है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पीवीसी पेस्ट रेजिन और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के मुद्दे की विस्तार से जांच की थी और यह माना गया है कि आयातित और घरेलू उत्पाद समान वस्तु है ।
- वर्तमान समीक्षा जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जैसा कि पूर्ववर्ती जांचों में परिभाषित किया गया है ।

ड.२. आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

12. लैदर क्लॉथ एंड प्लास्टिक्स मैन्यू एसो. (इंडिया) ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:

- पीवीसी पेस्ट रेजिन के दो प्रकार होते हैं, (क) सस्पेंशन ग्रेड और (ख) इमल्सन/पेस्ट ग्रेड । इमल्सन और सस्पेंशन ग्रेड के बीच एकमात्र अंतर पार्टीकल आकार के संबंध में होता है ।

- (ii) कैमप्लास्ट सनमार द्वारा पीवीसी रेजिन के सम्पेशन और इमल्सन दोनों प्रकारों का विनिर्माण किया जा रहा है। परंतु उसने पेस्ट/इमल्सन ग्रेड पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए आवेदन किया है जो पीवीसी रेजिन के कुल उत्पादन का तुलनात्मक रूप से एक छोटा भाग है।
- (iii) घरेलू उद्योग केवल एक ग्रेड अर्थात् 124 का विनिर्माण करता है जिसका उपयोग पीवीसी चर्म वस्त्र के उत्पादन में होता है।
- (iv) कैमप्लास्ट के पीवीसी पेस्ट रेजिन का उपयोग केवल सदस्यों द्वारा फॉम कोट के लिए किया जाता है। जबकि उपभोक्ता उच्चतम गुणवत्ता के पीवीसी पेस्ट रेजिन का आयात करते हैं। जिसका उपयोग टॉप कोट में किया जाता है। टॉप कोट तथा फॉम कोट के लिए पीवीसी पेस्ट रेजिन की जरूरत 30:70 के अनुपात में होती है। अतः उद्योग टॉप कोट रेजिन की अपनी जरूरत के न्यूनतम 30% का आयात करने के लिए बाध्य है।
- (v) ऐतिहासिक रूप से पीवीसी सम्पेशन तथा पीवीसी पेस्ट ग्रेड की कीमतों में लगभग 10-12 रुपए प्रति किग्रा का अंतर होता है। तथापि, आजकल पीवीसी सम्पेशन ग्रेड की कीमत लगभग 58-60 रुपए प्रति किग्रा है जबकि इमल्सन ग्रेड की कीमत 80-85 रुपए प्रति किग्रा है जिससे 25-27 रुपए प्रति किग्रा का असामान्य कीमत अंतर आ गया है।
- (vi) पीवीसी पेस्ट रेजिन पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पीवीसी सम्पेशन रेजिन की तुलना में पीवीसी पेस्ट रेजिन की कीमत संरचना में आगे और विकृति आएगी। पीवीसी सम्पेशन ग्रेड की तुलना में पीवीसी पेस्ट रेजिन के विनिर्माण में शामिल अतिरिक्त लागत केवल लगभग 6-7 रुपए प्रति किग्रा है।

13. इस मामले में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध दायर नहीं किया है।

उ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

- 14. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल मामले में विचाराधीन उत्पाद "पॉली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन" था जिसे इमल्सन पीवीसी रेजिन भी कहा जाता है और जिसका उल्लेख पीवीसी पेस्ट रेजिन के रूप में भी किया जाता है। वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) एक समान रहता है।
- 15. पीवीसी पेस्ट रेजिन का उत्पादन विनायल क्लोराइड मोनोमर (वीसीएम) से किया जाता है। वीसीएम का उत्पादन ई डी सी के उपयोग से किया जाता है जिसके लिए एक प्रमुख उत्पाद के रूप में क्लोरीन की जरूरत होती है। संबद्ध वस्तु का उत्पादन और विक्री सफेद/मट्टैले पाउडर के रूप में की जाती है। उत्पाद के गुणधर्मों का उल्लेख के मूल्य, अंतरनिहित श्लेषमक्ता, कणों के आकार की धारणीयता, तापक्षय, क्षय, प्रारंभिक बीएफबी आदि के रूप में किया जाता है। संबद्ध वस्तु के समस्त ग्रेड वर्तमान जांच की विषय वस्तु हैं और ये विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आते हैं। पीवीसी पेस्ट रेजिन का सामान्य अनुप्रयोग कृत्रिम चर्म, रेक्सीन, कोटेट फैब्रिक, तिरपाल, कन्वेयर बेल्टिंग, खिलौनों, ऑटोमोटिव सीलेंट, आसंजकों आदि में किया जाता है। संबद्ध वस्तु को डीओपी जैसे तरल प्लास्टिसाइजरों के मिश्रण द्वारा मुक्त प्रवाहमान मिश्रण तैयार करने के लिए उपभोक्ता के स्तर पर प्रसंस्कृत किया जाता है।

16. संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के उपशीर्ष सं. 39042210 के अंतर्गत वर्गीकृत है। मै. कैमप्लास्ट सनमार लि. ने यह दावा किया है कि आयातों की निकासी कई वर्गीकरणों में भी की गई है।

17. जहां तक 39042110 के अंतर्गत वर्गीकृत पॉलीविनायल क्लोराइड (सस्पेंशन ग्रेड) का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सस्पेंशन ग्रेड पीवीसी और पेस्ट ग्रेड पीवीसी के बीच भिन्नता और समानता की प्राधिकारी द्वारा जांच मूल जांच के समय विस्तार से की गई थी। किसी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा कोई नया साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है जिससे इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा निकाले गए पूर्ववर्ती निष्कर्ष की समीक्षा अपेक्षित हो जाती हो। प्रकटन विवरण के उत्तर में लैदर कलॉथ एंड प्लास्टिक्स मैन्यु एसो. ने अपने तर्कों की पुष्टि हेतु समय विस्तार की मांग की है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान कार्यवाही में यह अत्यंत विलंबित अनुरोध है। प्राधिकारी के लिए पाटनरोधी नियमानुसार निर्धारित समय सीमाओं के भीतर जांच पूरी करना अपेक्षित होता है। एसोसिएशन द्वारा अपने दावे की पुष्टि करते हुए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। तथापि, प्रकटन विवरण जारी होने के बाद नए तथ्यों को स्वीकार करने से अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान करना अपेक्षित हो सकता है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना/साक्ष्य का सत्यापन किया जा सकता है। यह नोट करना भी प्रासंगिक है कि वर्तमान जांच निर्णायिक समीक्षा जांच के स्वरूप की है। हितबद्ध पक्षकारों ने सस्पेंशन तथा पेस्ट पीवीसी रेजिन को अलग-अलग उत्पाद होने का दावा करते हुए मूल जांच के समय विस्तृत अनुरोध किए थे तथा प्राधिकारी ने दोनों को एक ही वस्तु नहीं पाया था। यह नोट करना भी प्रासंगिक है कि प्राधिकारी ने पूर्व में पी वी सी सस्पेंशन रेजिन के पाटन की जांच की थी जिसमें जांच का दायरा केवल पीवीसी सस्पेंशन रेजिन तक ही सीमित रखा गया था। एसोसिएशन द्वारा किसी भी हालत में जांच की एक वर्ष लंबी कार्यवाही के दौरान अपने तर्कों के समर्थन में संगत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। चूंकि एसोसिएशन के दावे अपुष्टिकृत रहते हैं, इसलिए प्राधिकारी का मत यह है कि पीवीसी सस्पेंशन ग्रेड रेजिन एक अलग उत्पाद है और यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आता है।

18. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पेस्ट पीवीसी रेजिन का उपयोग टॉप कोट तथा फॉम कोट में किया जा सकता है और यह कि घरेलू उद्योग पेस्ट पीवीसी रेजिन के एक ही प्रकार का उत्पादन करता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तर्क देते समय हितबद्ध पक्षकारों ने अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है। हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध क्षेत्र से आयातित पीवीसी पेस्ट रेजिन अथवा पीवीसी पेस्ट रेजिन के अलग-अलग ग्रेड भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिदेशन, कीमत, सीमाशुल्क वर्गीकरण आदि के आधार पर तुलनीय नहीं हैं। इसके विपरीत घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि उनके द्वारा उत्पादित और आपूर्त उसी ग्रेड का उपयोग इन उपभोक्ताओं द्वारा टॉप एवं फॉम दोनों प्रकार के कोट के लिए किया जाता है। घरेलू उद्योग ने आगे यह तर्क दिया है कि वस्तुतः चर्म वस्त्र की तीन परतें, टॉप कोट, बेस कोट और फॉम कोट होती हैं और ये तीनों कोट उपभोक्ताओं द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्त पीवीसी पेस्ट के समान ग्रेड के उपयोग से तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग आयातित ग्रेडों से तुलनीय ग्रेडों की आपूर्ति नहीं करता है परंतु उन्होंने अपने दावे का समर्थन नहीं किया है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि इसी

प्रकार के तर्क मूल जांच के समय भी दिए गए थे परंतु प्राधिकारी ने जांच के दायरे से इन ग्रेडों को अलग रखने में पर्याप्त औचित्य नहीं पाया था ।

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा जांच के स्वरूप की है और इसीलिए विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र सामान्यतः वहीं रहेगा जैसा कि मूल जांच में था बशर्ते कोई हितबद्ध पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को सीमित करने की जरूरत की पुष्टि न कर दे । प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि उत्पाद पीवीसी पेरस्ट रेजिन के कई ग्रेड और उप-प्रकार हैं तथापि, इन सभी की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं तथा अंतिम उपयोग एक समान हैं भले ही के मूल्य तथा अन्य मापदंडों के संबंध में विनिर्देशन इन ग्रेडों के उत्पादन हेतु विनिर्माताओं द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं । यह सिद्ध करने के लिए किसी हितबद्ध पक्षकार ने कोई वास्तविक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि ये अलग-अलग ग्रेड एक-दूसरे ग्रेड के समान वस्तु नहीं हैं । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध इस तर्क पर आधारित हैं कि घरेलू उद्योग समान ग्रेडों का उत्पादन नहीं करता है । तथापि, यह सिद्ध नहीं किया गया है कि ये ग्रेड भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं तथा तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता के संबंध में उत्पादित ग्रेडों के समान नहीं हैं ।
20. अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि अलग-अलग ग्रेडों के पीवीसी रेजिन का भारत में आयात किया जा रहा है और हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध करने के लिए रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं रखा है कि पीवीसी रेजिनों के अलग-अलग ग्रेड अलग-अलग उत्पाद हैं और ये तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं । अतः प्राधिकारी इन ग्रेडों को अलग रखने के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क में कोई आधार नहीं पाते हैं । अतः प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है ।

च. घरेलू उद्योग का आधार तथा क्षेत्र विस्तार

- च.1. मै.कैमप्लास्ट सनमार लि., चेन्नई द्वारा किए गए अनुरोध
21. मै. कैमप्लास्ट सनमार लि. भारत में संबद्ध वस्तु का एक प्रमुख उत्पादक है जिसका भारतीय उत्पादन में 78.97 % हिस्सा है । कंपनी पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर "आधार" की अपेक्षा की पूर्ति करती है और वह "घरेलू उद्योग" है ।
- च.2. आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध
22. लेदर क्लॉथ एंड प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एलसीएमपीए) (इंडिया) ने अनुरोध दायर किए हैं । किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध दायर नहीं किया है । "घरेलू उद्योग" के संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है ।
23. मै. एलसीएमपीए (इंडिया) ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि भारत में संबद्ध वस्तु का सिर्फ एक ही उत्पादक है ।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

24. इस समीक्षा जांच की शुरुआत के समय पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नानुसार उपबंध है:-

"ख" घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाठित वस्तु के नियर्तकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा ।

तथापि, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में हाल ही में संशोधन किया गया है जो निम्नानुसार है:

"ख" घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाठित वस्तु के नियर्तकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा ।

25. वर्तमान समीक्षा जांच में मै. कैमप्लास्ट सनमार लि. ने जांच शुरुआत संबंधी सूचना का उत्तर दिया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. कैमप्लास्ट सनमार लि. भारत में संबद्ध वस्तु का एक प्रमुख उत्पादक है क्योंकि उसका हिस्सा कुल भारतीय उत्पादन का 78.97% है । अतः मै. कैमप्लास्ट सनमार लि. पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर "आधार" की अपेक्षा की पूर्ति करती है और वह "घरेलू उद्योग" है ।

छ. पाटन निर्धारण

सामान्य मूल्य

छ.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

26. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि ई यू के उत्पादकों द्वारा भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है । उनके द्वारा यूरोपीय संघ में घरेलू बाजार में प्रचलित पीवीसी पेस्ट/इमल्सन रेजिन की कीमतों के बारे में सूचना प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे; परंतु उनके घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की वास्तविक सौदे-वार बिक्री कीमत (उत्पादक तथा थोक विक्रेता/वितरक के बीच) के बारे में कोई तर्कसम्मत, प्रामाणिक और सही सूचना प्राप्त नहीं की जा सकी ।

27. उन्होंने प्रकाशित पत्रिकाओं में संबद्ध वस्तु की कीमतों का पता लगाने का प्रयास भी किया था । इस व्यापार में हरीमन कैमसल्ट लि. की "विनायल क्लोराइड" एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत, अत्यधिक भरोसेमंद प्रामाणिक पत्रिका है और वे इस पत्रिका के आधार पर संबद्ध देश के घरेलू बाजार में कीमतों से संबंधित सूचना हासिल करने में समर्थ हो गए हैं ।
28. इसके मद्देनजर संबद्ध क्षेत्र में सामान्य मूल्य का आकलन इस पत्रिका में सूचित कीमतों के आधार पर किया गया है ।

छ.2. निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

29. किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक ने निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है । मैं, कैमप्लास्ट सनमार लि. ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि पाटन मार्जिन ई यू में घरेलू बिक्री कीमत पर आधारित होना चाहिए; जबकि लैदर क्लॉथ एंड प्लास्टिक्स मैन्यु. एसो. ने यह अनुरोध किया है कि हरीमन कैमसल्ट लि. की पत्रिका "विनायल क्लोराइड" में प्रकाशित कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना उचित नहीं होगा ।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

30. इस जांच में ई यू के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है । ई यू के निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा असहयोग को देखते हुए प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना और तथ्यों पर विचार किया है । प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के इस दावे को नोट किया है कि उनके द्वारा ई यू के घरेलू बाजार में प्रचलित संबद्ध वस्तु की कीमत के बारे में सूचना प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे परंतु वे घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की वास्तविक सौदेवार बिक्री कीमत के बारे में कोई तर्कसम्मत, प्रामाणिक अथवा सही सूचना प्राप्त नहीं कर सके थे ।

ई यू के निर्यातकों/उत्पादकों की ओर से असहयोग को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का परिकलन किया है । इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि, संबद्ध वस्तु की कीमतें हरीमन कैमसल्ट लि. द्वारा प्रकाशित "विनायल क्लोराइड" नामक पत्रिका में नियमित रूप से प्रकाशित की जाती हैं परंतु कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि इस पत्रिका में प्रकाशित संबद्ध वस्तु की कीमतें पीवीसी के ग्रेडों में अंतर और उनकी तदनुरूपी कीमतों में अंतर के कारण भरोसेमंद नहीं हो सकती हैं । वर्तमान मामले में ई यू के निर्यातकों/उत्पादकों के असहयोग को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी के पास सामान्य मूल्य के निर्धारण की पद्धति का सहारा लेने के सिवाय विकल्प बहुत कम बचा है । अतः प्राधिकारी ने प्रमुख कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, घरेलू उद्योग के खपत कारक तथा घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत पर विचार करते हुए ई यू के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है और इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य *** अम.डॉ. प्रति मी.ट. बनता है ।

ज.4. निर्यात कीमत

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंयू के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने इस जांच में प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। इंयू के निर्यातकों/उत्पादकों के असहयोग को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना और तथ्यों पर विचार किया है।

32. विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों के असहयोग को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया है कि क्या आई बी आई एस और डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रदत्त आयात के आंकड़ों का उपयोग संगत अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत के निर्धारण में किया जा सकता है। इस प्रकार प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद की भारित औसत आयात कीमत निर्धारित की है।

33. घरेलू उद्योग ने आई बी आई एस द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर मात्रा, मूल्य और आयात कीमत निर्धारित की है। प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से भी आंकड़े मांगे थे; जिनके विश्लेषण से यह पता चला कि जांच अवधि के दौरान डीजीसीआईएंडएस द्वारा सूचित आयात की मात्रा आई बी आई एस द्वारा सूचित आयात की मात्रा से काफी कम थी। अतः प्राधिकारी ने सर्वप्रथम सीमाशुल्क वर्गीकरणवार और तत्पश्चात सीमाशुल्क पत्तनवार मात्रा और दोनों स्रोतों में सूचित आयात के मूल्य के अनुसार दोनों आंकड़ों का मिलान किया और उनकी तुलना की।

34. यह देखा गया है कि दोनों स्रोतों में सूचित मात्राओं में भारी अंतर है। एक बड़ा अंतर कोचीन पत्तन में सूचित आयात के आंकड़ों में देखा गया है। इसके अलावा, वर्गीकरणवार आयातों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि अन्य वर्गीकरणों (खासकर 3904 2110 के अंतर्गत) में भारी अंतरों को सूचित किया गया है।

35. इसके मद्देनजर प्राधिकारी ने वर्तमान निर्धारण के प्रयोजनार्थ मात्रा, मूल्य और आयात कीमत के निर्धारण हेतु आई बी आई एस द्वारा सूचित आयात के आंकड़ों को अपनाया है क्योंकि आई बी आई एस के आंकड़ों में दर्शायी गई मात्रा काफी अधिक है जबकि प्रति इकाई कीमत दोनों स्रोतों में लगभग समान है।

36. आई बी आई एस में सूचित कीमतें सीआईएफ आयात कीमतें हैं। इंयू के उत्पादकों/निर्यातकों के असहयोग के मद्देनजर प्राधिकारी ने भारत के लिए कारखाना निर्यात कीमत निकालने हेतु सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर कीमत समायोजन किए हैं। अतः कीमत समायोजन समुद्री एवं अंतरदेशीय भाड़े, पत्तन हैंडलिंग तथा समुद्री बीमा के संबंध में किए गए हैं। प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ के सभी निर्यातकों अथवा उत्पादकों के लिए संबद्ध वस्तु की कारखाना निर्यात कीमत का निर्धारण निम्नानुसार किया है:

विवरण	इकाई	यूरोपीय संघ
आयात मात्रा	मी.ट.	3,374
आयात मूल्य	लाख रुपए में	1,766.44

सीआईएफ निर्यात कीमत	रु./मी.ट.	52,354
परिवर्तन दर	रु./अम.डॉ.	45.72
सीआईएफ निर्यात कीमत अम.डॉ. में	रु./अम.डॉ.	1,145.08
कीमत समायोजन (योग)	रु./अम.डॉ.	***
कारखानागत निर्यात कीमत	रु./अम.डॉ.	***

झ. पाटन मार्जिन

37. चूंकि ई यू के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने इस जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है, इसलिए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातकों/उत्पादकों के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सकता। अतः प्राधिकारी ने ई यू से संबद्ध वस्तु के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है। कारखाना स्तर पर ऊपर स्पष्ट किए गए अनुसार निर्धारित सामान्य मूल्य एवं निवल निर्यात कीमत के आधार पर संबद्ध क्षेत्र के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए जांच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन का निम्नानुसार निर्धारण किया गया है :

	इकाई	यूरोपीय संघ
सामान्य मूल्य	अम.डॉ./मी.ट.	***
निर्यात कीमत	अम.डॉ./मी.ट.	***
पाटन मार्जिन रेंज	अम.डॉ./मी.ट.	300-320
पाटन मार्जिन	%	27.73%

झ. पाटन जारी रहना या उसकी पुनरावृत्ति होना

38. यद्यपि, ई यू के किसी उत्पादक/निर्यातक से कोई उत्तर नहीं मिला है, तथापि, घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:

(क) ई यू के उत्पादकों/निर्यातकों ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है और निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से सूचना नहीं दी है।

(ख) प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा हेतु विशिष्ट अतिरिक्त अपेक्षाएं निर्धारित की हैं। ई यू के उत्पादकों/निर्यातकों ने इस प्रश्नावली का भी उत्तर नहीं दिया है।

(ग) पाटनरोधी शुल्क की अंवधि बढ़ाने का विरोध करने वाले किसी अन्य पक्षकार ने भी इस संबंध में प्राधिकारी को कोई सूचना प्रदान नहीं की है ।

(घ) यूरोपीय संघ से पाटन मार्जिन अत्यधिक है । यूरोपीय संघ से पाटन पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद समाप्त नहीं हुआ है ।

(ङ) विचाराधीन उत्पाद का भारी मात्रा में निर्यात जारी है और वर्तमान निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन अत्यधिक है ।

(च) यूरोप के उत्पादक कई देशों को इस उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं । पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद ई यू से आयातों में वृद्धि हुई है ।

(छ) ई यू के उत्पादकों के पास पर्याप्त बेरी क्षमताएं मानी जाती हैं ।

(ज) यद्यपि, उत्पादकों द्वारा सामान्य तौर पर अनन्य आधार पर सर्पेंशन एवं पेस्ट पीवीसी के बीच उत्पादन सुविधाओं का उपयोग किया जाता है, तथापि, यह संभव है कि उत्पादक सर्पेंशन पी वी सी क्षमताओं का उपयोग पी वी सी पेस्ट रेजिन के उत्पादन में अथवा न्यूनतम प्रयासों के साथ इसके प्रतिकूल करें । इस प्रकार सर्पेंशन पी वी सी क्षमताओं का उपयोग पी वी सी पेस्ट रेजिन में किए जाने से इंकार नहीं किया जाता है ।

39. उपर्युक्त के मद्देनज प्राधिकारी यह मानते हैं कि लागू पाटनरोधी उपाय को समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध वस्तु का पाटन जारी रहने की संभावना है ।

ट. क्षति

ट.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

40. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोध संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

(क) संबद्ध क्षेत्र तथा अन्य प्रमुख देशों से भारत को विचाराधीन उत्पाद का पाठित कीमतों पर निर्यात जारी है ।

(ख) मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पाटन जारी रहा है ।

(ग) घरेलू उद्योग उत्तीर्णी सीमा तक अपना निष्पादन सुधारने में समर्थ नहीं रहा है जिस सीमा तक वह सुधार सकता था ।

(घ) संबद्ध क्षेत्र तथा अन्य पाटनकर्ता देशों से हुए आयातों में भारत में कुल आयात, उत्पादन तथा खपत की तुलना में वृद्धि हुई है ।

(ङ) उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री, मूल्य एवं मात्रा, लाभ, निवेश पर आय, नकद प्रवाह तथा बाजार हिस्से के रूप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है ।

(च) अत्यधिक मांग होने के बावजूद घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग ईष्टतम से कम बना हुआ है ।

(छ) जारी पाटित आयात घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से अत्यधिक कम कीमत पर हो रहे हैं जिसकी वजह से संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमत का ह्रास हुआ है ।

(ज) घरेलू उद्योग को सतत वास्तविक क्षति हुई है ।

(झ) कच्ची सामग्री की कीमत बढ़ जाने के कारण क्षतिकारी पाटन को रोकने के लिए पाटनरोधी शुल्क का वर्तमान स्तर अत्यंत अपर्याप्त है ।

(ञ) वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन पर विचार करते हुए पाटनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ाना अपेक्षित है ।

ट.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

41. मै. मयूर यूनीकोटर्स लि. (प्रकटन विवरण के उत्तर में) तथा लैदर क्लॉथ एंड प्लास्टिक मैन्यु. एसो. ने उत्तर दायर किए हैं। किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है। इस्यु के किसी उत्पादक/निर्यातक ने कोई उत्तर नहीं दिया है न ही क्षति एवं कारणात्मक संबंध सहित वर्तमान जांच के किसी पहलू के बारे में कोई तर्क दिया गया है।

42. मै. लैदर क्लॉथ एंड प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसो. (इंडिया) ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि :

- कैम प्लास्ट सनमार्क के पीवीसी संयंत्र में खासकर वर्ष 2008-09 और चालू वर्ष में बार-बार खराबी आई है/वह बंद रहा है। इसके परिणामस्पर्श कैमप्लास्ट देश में पीवीसी पेस्ट रेजिन की संपूर्ण मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं रहा है।
- पीवीसी पेस्ट रेजिन की प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमत 400 अम.डॉ. से 1500 अम.डॉ. प्रति टन के बीच रही है और पहुंच कीमत कैमप्लास्ट की 79-80 रुपए की प्रचलित घरेलू कीमत की तुलना में 85-87 रु. प्रति किग्रा. बनती है। यूरोपीय संघ से पिछले दो-तीन वर्ष में कैमप्लास्ट सनमार्क की कीमत से कम कीमत पर कोई आयात नहीं किया गया है।
- पीवीसी पेस्ट रेजिन का हिस्सा पीवीसी कोटेड फैब्रिक के विनिर्माण हेतु कच्ची सामग्री की लागत का लगभग 40% होता है। चीन, ताईवान तथा कोरिया से पीवीसी कोटेड फैब्रिक का बड़ी मात्रा में आयात किया गया है। यदि पी वी सी पेस्ट रेजिन पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाएगा तो पीवीसी कोटेड फैब्रिक के विनिर्माता जीवित नहीं रहेंगे। पी वी सी पेस्ट रेजिन पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू लघु पी वी सी कोटेड फैब्रिक उद्योग आयातों के मुकाबले अप्रतिस्पर्धी बन जाएगा और कई इकाइयां बंद होने के लिए बाध्य हो जाएंगी। पी वी सी प्रसंस्करण इकाइयां मुख्यतः लघु क्षेत्र में हैं जो देश भर में 1 लाख से अधिक कामगारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रही हैं।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

43. मै. लेदर क्लॉथ एंड प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसो. (इंडिया) ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि मै. कैमप्लास्ट के संयंत्र में खासकर वर्ष 2008-09 के दौरान बार-बार खराबी आई है अथवा वह बंद हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप कंपनी मांग को पूरा नहीं कर सकी है। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने वर्ष 2008-09 के दौरान मै. कैमप्लास्ट के माहवार उत्पादन की जांच की और उसकी तुलना उसी अवधि के दौरान आयात की मात्रा से की। यह देखा गया कि कंपनी ने जांच अवधि के दौरान सभी महीनों में वस्तु का उत्पादन किया है। स्पष्टतः आयात की मात्रा का कंपनी के उत्पादन की प्रवृत्ति से कोई सह-संबंध नहीं है। इसके अलावा, आयात की मात्रा कंपनी की उत्पादन मात्रा में आई गिरावट से काफी अधिक है। अतः इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है कि संयंत्र के बार-बार खराब होने अथवा बंद होने के कारण आयात जरूरी हो गए थे।

माह	उत्पादन मी.ट. में	उत्पादन सूचीबद्ध	भारत में आयात मी.ट. में
अप्रैल 08	***	100	1078
मई 08	***	83	2117
जून 08	***	79	1934
जुलाई 08	***	85	2482
अगस्त 08	***	74	5382
सितं. 08	***	68	1761
अक्टू. 08	***	89	621
नवं. 08	***	88	664
दिसं. 08	***	85	1221
जन. 09	***	90	1561
फर. 09	***	76	2859
मार्च 09	***	89	1594

44. प्रकटन विवरण के उत्तर में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

प्रकटन विवरण के उत्तर में मै. कैमप्लास्ट सनमार लि. तथा लेदर क्लॉथ एंड प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसो. (इंडिया) ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:

45. मै. कैम्प्लास्ट सनमार लि. के अनुरोध

- क्षति एवं उसकी संभावना के दावे के समर्थन में घरेलू उद्योग ने सेस्टेट के निर्णयों का हवाला दिया है ।
- पाटनरोधी शुल्क निर्धारित मात्रा में होना चाहिए । शुल्क का पूर्ववर्ती स्वरूप न तो उचित था और न ही घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले पाटन को रोकने में सक्षम था ।
- पाटनरोधी शुल्क अम.डॉ. में होना चाहिए ।

46. लेदर टेक्टाइल एंड प्लास्टिक मैन्यु. एसोसिएशन (इंडिया) द्वारा किए गए अनुरोध

- पेस्ट रेजिन की उत्पादन लागत का निर्धारण करने के लिए सस्पेंशन रेजिन की उत्पादन लागत को भी घरेलू उद्योग के आंकड़ों में रखा जाना चाहिए क्योंकि कच्ची सामग्री 100% एक समान है ।
- घरेलू विनिर्माताओं की लाभप्रदता में गिरावट उत्पादन सुविधाओं के अपर्याप्त उपयोग सहित कई कारणों से आ सकती है ।
- यह स्पष्ट प्रदर्शन अत्यंत धोखाधड़ीपूर्ण है कि घरेलू उद्योग के उत्पादकता में गिरावट आई है । मामले की वास्तविकता यह है कि कैम्प्लास्ट सस्पेंशन रेजिन तथा पेस्ट रेजिन दोनों का उत्पादन कर सकता है और वह एक दूसरे को आसानी से तैयार कर सकता है । अतः किसी को भी वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए सस्पेंशन रेजिन तथा पेस्ट रेजिन दोनों की उत्पादकता पर गौर करना चाहिए ।
- उन्होंने प्राधिकारी के समक्ष आगे कारगर प्रस्तुतिकरण हेतु संगत आंकड़े जुटाने के लिए लगभग दो माह के समय विस्तार की मांग की है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

47. प्राधिकारी ने क्षति जांच से संबंधित तर्कों को नोट किया है और इन मुद्दों का समाधान उचित स्थानों पर किया है । प्राधिकारी ने तथ्यों तथा हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की तथ्यपरक जांच की है ।

48. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव ; तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच करने का उपबंध है । पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के

प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती ।

49. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निम्नानुसार उल्लेख है :

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट, सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा ।"

50. "क्षति" निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने इस से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा और घरेलू उद्योग पर उसके कीमत प्रभाव तथा कीमत एवं लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जांच की है ताकि क्षति एवं पाटन एवं क्षति, यदि कोई हो, के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी की जांच की जा सके ।

51. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा चीन जन.गण., जापान, कोरिया गण, मलेशिया, रूस, ताईवान और थाईलैंड के उत्पादकों द्वारा संबद्ध वस्तु के पाटनों का आरोप लगाते हुए एक पाटनरोधी आवेदन दायर किया गया था ; और यह कि प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद प्राधिकारी ने इन देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बारे में 3 नवंबर, 2009 की अधिसूचना द्वारा पाटनरोधी जांच शुरू की थी ।

ट.3.1. मात्रात्मक प्रभाव

(क) मांग का निर्धारण

52. संबद्ध वस्तु की घरेलू खपत/मांग का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग तथा अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री मात्रा को भारत में हुए कुल आयातों में जोड़ा गया है जिनका उल्लेख संक्षेप में निम्नानुसार है:

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जांच अवधि)
संबद्ध देश से आयात	मी.ट.	840	891	292	3,374
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	3,927	4,158	6,337	19,900
कुल आयात	मी.ट.	4,767	5,049	6,629	23,274
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	30,733	29,184	27,664	23,269

अन्य भारतीय उद्योग की बिक्री	मी.ट.	3,195	4,891	5,402	5,997
मांग	मी.ट.	38,695	39,124	39,695	52,540

प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है और आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान इसमें पर्याप्त वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान मांग में वृद्धि लगभग 35.78 % की हुई है।

ख) आयात मात्रा तथा बाजार हिस्सा

53. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (ii) में यह उपबंध है कि : "पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है ..."। अतः जहां तक पाटित आयातों की मात्रा का संबंध है, इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

54. निम्नलिखित तालिका में आयात की मात्रा और बाजार हिस्से से संबंधित स्थिति का सारांश दिया गया है: -

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जांच अवधि)
निम्नलिखित देश से आयात					
यूरोपीय संघ	मी.ट.	840	891	292	3,374
जांचाधीन अन्य देशों से आयात	मी.ट.	3,636	3,740	6,313	19,020
कुल आयात	मी.ट.	4,767	5,049	6,629	23,274
भारतीय उत्पादन	मी.ट.	33,703	34,636	32,442	29,439
मांग	मी.ट.	38,694	39,124	39,695	52,540
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
कुल आयात	%	17.62%	17.64%	4.40%	14.50%
उत्पादन	%	2.49%	2.57%	0.90%	11.46%
खपत	%	2.17%	2.28%	0.73%	6.42%
मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	79.42%	74.59%	69.69%	44.29%

उपरोक्तानुसार प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- (i) ई यू से पाटित आयातों की मात्रा, जिसमें 2007-08 के दौरान कमी आई थी, जांच अधिकारी के दौरान लगातार वृद्धि हुई है।
- (ii) ई यू से हुए आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद आयातों में वृद्धि हुई है।
- (iii) भारत में कुल आयात, उत्पादन और खपत की तुलना में जांच अधिकारी से हुए आयातों में भारी वृद्धि हुई है।
- (iv) आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के हिस्से में अत्यधिक गिरावट आई है।

ट.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

55. घरेलू उद्योग पर ई यू से हुए संबद्ध वस्तु के आयातों के कीमत प्रभाव का पता लगाने के लिए प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमत में अन्यथा इतनी अधिक मात्रा तक गिरावट आई है अथवा होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती। कीमत कटौती की मात्रा का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना आयातों की पहुंच कीमत के साथ की है। निवल बिक्री प्राप्ति की गणना सभी रिबेटों और करों की कटौती करने के बाद की गई थी। आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना लागू पाटनरोधी उपाय पर विचार करने के बाद भी घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ की गई थी। लागू सीमाशुल्क तथा सीमाशुल्क पर उपकर सहित ई यू से पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से काफी कम है। इसके अलावा, अन्य देशों से उत्पाद के अत्यधिक आयातों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने जांचाधीन तीसरे देशों से हुए इन आयातों के संबंध में अलग से कीमत कटौती का निर्धारण किया है।

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जांच अधिकारी)
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	108	116
पाटनरोधी शुल्क बैंचमार्क	रु./मी.ट.	42,230	43,363	38,755	43,478
यूरोपीय संघ से औसत पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	42,475	50,243	54,307	55,077
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	128	130
कीमत कटौती राशि	रु./मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती रेंज	% रेंज	20-25	5-10	0-5	5-10
जांचाधीन से इतर अन्य देशों से आयातों की औसत पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	54579	51951	49563	56453
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	91	103
कीमत कटौती राशि	रु./मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती रेंज	% रेंज	Negative	5-10	10-15	5-10

उपरोक्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

- (i) ई यू से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में अत्यधिक कटौती हो रही है ।
- (ii) घरेलू उद्योग की कीमत तथा आयमत कीमत में भारी अंतर होने के कारण जांच अवधि में आयात मात्रा में वृद्धि हुई है ।
- (iii) यद्यपि, सी आई एफ कीमत में वृद्धि होने के कारण पहुंच कीमत बढ़ी है, परंतु प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सीआईएफ कीमत में हुई वृद्धि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में हुई वृद्धि से कम रही थी, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से दो जा सकेगा ।
- (iv) जांचाधीन अन्य देशों से अलग-अलग हुए आयात के कारण भी घरेलू उद्योग की कीमत में भारी कटौती हो रही है ।

कीमत हास/न्यूनीकरण

56. इस बात का निर्धारण करने के लिए कि क्या ई यू से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत का ह्रास हुआ है, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान आयातों की पहुंच मूल्य के साथ-साथ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत तथा निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना की है जिसका उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है :

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जांच अवधि)
उत्पादन की लागत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	122	135
निवल बिक्री कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	108	116
लाभ/हानि	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(171)	(352)	(442)
ई यू से आयातकों की औसत पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	42,397	50,171	54,229	54,998
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	128	130
जांचाधीन अन्य देशों से आयात की औसत पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	54,479	51,876	49,492	56,372
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	91	103

प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि, क्षति अवधि के दौरान उत्पादन लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है, तथापि, निवल बिक्री में वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि से काफी कम रही थी । अतः आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में भारी ह्रास हो रहा है ।

घरेलू उद्योग के संबंध में आर्थिक मापदंड

57. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के विश्लेषण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा ।

उत्पादन, बिक्री, क्षमता तथा क्षमता उपयोग

58. घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री, क्षमता एवं क्षमताउपयोग निम्नानुसार रहा है:

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जांच अवधि)
क्षमता	मी.ट.	34,080	34,080	34,080	34,080
उत्पादन	मी.ट.	30,789	29,117	27,584	23,249
क्षमता उपयोग	%	90.34%	85.44%	80.94%	68.22%
घरेलू बिक्री	मी.ट.	30,733	29,184	27,664	23,269
मांग	मी.ट.	38,695	39,124	39,695	52,540
मांग के % के रूप में उत्पादन	%	79.57%	74.42%	69.49%	44.25%
मांग के % के रूप में बिक्री	%	79.42%	74.59%	69.69%	44.29%

यह नोट किया जाता है कि:

- (क) घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में समग्र रूप में गिरावट आई है ।
- (ख) घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में भारत में उत्पाद की मांग/खपत की तुलना में गिरावट आई है ।

(ग) घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि भारत में उत्पाद की मांग में हुई वृद्धि के अनुरूप होनी चाहिए थी। तथापि, उत्पाद के पाटन के कारण इन मापदंडों में गिरावट आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि अथवा क्षमता की सीमा तक अपने उत्पादन को बढ़ाने में समर्थ नहीं हुआ है।

(घ) घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में भारत में उत्पाद की मांग की तुलना में भारी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन क्षमताओं का उपयोग करने में समर्थ नहीं रहा है।

लाभप्रदता

59. घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति तथा लाभ/हानि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
उत्पादन की लागत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./मी.ट.	***	***	***	***
लाभ/हानि	रु./मी.ट.	***	***	***	***
घरेलू उद्योग पर कर पूर्व लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
घरेलू बिक्री पर पीबीआईटी	लाख रुपए	***	***	***	***

60. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के बारे में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई और उसे भारी घाटा हुआ। प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन लागत और बिक्री कीमत के रुद्धानों पर विचार करने के बाद लाभप्रदता की जांच की। यह पाया गया कि समूची क्षति अवधि के दौरान उत्पादन लागत तथा बिक्री कीमत में वृद्धि हुई। परंतु उत्पादन लागत में वृद्धि बिक्री कीमत में हुई वृद्धि से काफी अधिक रही है। परिणामतः जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

61. घरेलू उद्योग को हो रहे लगातार घाटे के मद्देनजर जिसमें वर्तमान क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, प्राधिकारी ने खासकर इंयू से हुए आयातों पर पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को देखते हुए घरेलू उद्योग को हुए सतत वित्तीय घाटे के कारणों की जांच की थी। यह नोट किया जाता है कि पूर्व में पाटनरोधी शुल्क बैंचमार्क कीमत के रूप में लगाया गया था। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद संबद्ध वस्तु की आयात कीमत में एडीडी बैंच मार्क की तुलना में भारी वृद्धि हुई होती यदि आयातों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया होता। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह प्रदर्शित करने के लिए साक्ष्य उपलब्ध कराया है कि आयात कीमत में वृद्धि पाटन की समाप्ति की वजह से नहीं हुई है परंतु यह वृद्धि कच्ची सामग्री की लागत में हुई भारी वृद्धि के कारण हुई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वस्तुतः आयात कीमत में वृद्धि कच्ची सामग्री की वजह से लागत में हुई वृद्धि से काफी कम रही थी और यह कि शुल्क के स्वरूप के कारण पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद पाटित कीमतों पर उत्पाद का सतत आयात हो रहा है।

62. यह भी नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात कई अन्य देशों से किया जा रहा है। इसके अलावा, विभिन्न स्रोतों से आयात कीमत आयात की पर्याप्त मात्रा के संबंध में तुलनीय है। चीन जन.गण., जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, रूस, ताईवान और थाईलैंड से आयात प्रथम दृष्ट्या पाटित कीमतों पर हुए हैं। जिसके संबंध में प्राधिकारी अलग से पाटनरोधी जांच कर रहे हैं। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु का पाटन करने वाले विभिन्न स्रोतों से क्षति अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम रही है और इस प्रकार कीमत में सतत कटौती हुई है। कीमत में अत्यधिक कटौती होने के कारण घरेलू उद्योग उस कीमत को वसूलने से वंचित हुआ है जिससे वह उत्पादन लागत की उचित प्राप्ति हेतु वसूल कर सकता था। आगे यह नोट किया जाता है कि जहां समूची क्षति अवधि के दौरान लागत में वृद्धि हुई है और यद्यपि बिक्री कीमत में भी वृद्धि हुई है परंतु बिक्री कीमत में वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि से काफी कम रही है।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध क्षेत्र और अन्य स्रोतों से उत्पाद के सतत पाटन से स्पष्टः समूची क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हुआ है।

बाजार हिस्सा

63. घरेलू उत्पादकों की बिक्री और ई यू तथा विभिन्न अन्य स्रोतों से हुए आयातों की तुलना से यह पता चलता है कि यद्यपि उत्पाद की मांग में सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है तथापि ई यू एवं अन्य देशों से हुए संबद्ध आयातों के हिस्से में वृद्धि होने के कारण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है।

मांग में बाजार हिस्सा	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जांच अवधि)
संबद्ध देश-यूरोपीय संघ	%	2.17%	2.28%	0.73%	6.42%
अन्य देश	%	10.15%	10.63%	15.96%	37.88%
घरेलू उद्योग	%	79.43%	74.59%	69.69%	44.29%
अन्य घरेलू उत्पादक	%	8.25%	12.50%	13.62%	11.41%

रोजगार तथा मजदूरी

64. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित स्थिति निम्नानुसार है :

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जांच अवधि)
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
मजदूरी	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रति दिवस उत्पादकता	मी.ट./दिवस	***	***	***	***
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट.	***	***	***	***

प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन में गिरावट के साथ-साथ घरेलू उद्योग की उत्पादकता में गिरावट आई है । उत्पादकता में गिरावट के अंतिम परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है । तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी है और इस प्रकार घरेलू उद्योग में रोजगार तथा प्रदत्त मजदूरी वर्तमान मामले में हुई क्षति का मूल्यांकन करने का कोई सही मापदंड नहीं हो सकता है ।

निवेश पर आय तथा नकद प्रवाह

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निवेश पर आय तथा नकद लाभ की स्थिति में गिरावट आई है । ऐसी ही स्थिति नकद लाभ के मामले में भी है ।

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जांच अवधि)
आरओआई - जीएफए आधार	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	(100)	(203)	(340)	(363)
आरओआई - एनएफए आधार	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	(100)	(219)	(358)	(400)
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	(100)	(162)	(316)	(335)
नकद प्रवाह	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	(100)	(50)	(601)	(421)

मालसूची

66. घरेलू उद्योग की मालसूची में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है ।

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
औसत मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***

घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में गिरावट बाजार में पाटित आयात की मौजूदगी के मद्देनजर घरेलू उद्योग के उत्पादन में कमी के परिणामस्वरूप आई है ।

पाटन मार्जिन की मात्रा

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस से पाटन मार्जिन काफी अधिक है । जांच अवधि में अत्यधिक पाटन मार्जिन इस से के निर्यातकों के संभावित भावी व्यवहार का भी द्योतक है ।

वृद्धि

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि, संबद्ध देश से आयात मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है ; परंतु बिक्री, उत्पादन तथा क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि ऋणात्मक रही है । क्षति अवधि के दौरान नकद लाभ, लाभ एवं निवेश पर आय में वृद्धि भी ऋणात्मक रही है ।

सतत पाटन और क्षति की संभावना

69. घरेलू उद्योग को हुई क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करने के लिए प्राधिकारी के समक्ष निम्नलिखित कारक लाए गए हैं । घरेलू उद्योग ने यह दलील दी है कि किसी निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी के लिए पाटन की समाप्ति हेतु शुल्क जारी रखने या उसकी मात्रा में घट-बढ़ करने या उसे समाप्त करने का फैसला करने के लिए पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करना अपेक्षित होता है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि :

- इस से हुई क्षति अभी भी जारी है और यदि शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति में वृद्धि होने की संभावना है ।
- ईसे हुए आयातों की पहुंच कीमत उस उचित बिक्री कीमत से काफी कम है जिसे घरेलू उद्योग को प्राप्त करना चाहिए था ।
- मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद यूरोपीय संघ से आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है ।

(v) घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उत्पादकों के पास पर्याप्त बेशी क्षमताएं हैं और उनकी घरेलू मांग उनके द्वारा सृजित क्षमताओं से काफी कम है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस दावे का खंडन किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने नहीं किया है।

क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन:-

70. प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की क्षति रहित कीमत की तुलना जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु ई यू से हुए निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। इस प्रकार की गई तुलना से क्षति मार्जिन की गणना निम्नानुसार की गई है :

एनआईपी	रु./मीट	***
पहुंच कीमत	रु./मीट	54,998
क्षति मार्जिन	रु./मीट	***
क्षति मार्जिन (%)	%	20-25%

क्षति के संबंध में निष्कर्ष

71. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद ई यू से पाटित आयात जारी है और न केवल उसकी मात्रा में समग्र रूप में वृद्धि हुई है अपितु मात्रा में हुई वृद्धि भारत में संबद्ध वस्तु की कुल खपत में उसके हिस्से के संबंध में भी हुई है। इसके अलावा, आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत में भारी कटौती हो रही है। इसके अतिरिक्त, आयातों से कीमत में भारी हास हो रहा है। हालांकि उत्पादन लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है तथापि, बिक्री कीमत में वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि से काफी कम रही है। घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता, उपयोगिता, लाभ, निवेश पर आय, नकद प्रवाह, उत्पादकता के संबंध में गिरावट आई है। अतः प्राधिकारी का यह मत है कि घरेलू उद्योग को मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद वास्तविक क्षति हो रही है।

72. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी का मानना है कि:

- (क) पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने अथवा उसे निररत किए जाने की स्थिति में ई यू से भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात उसके संबद्ध सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किए जाने की संभावना है।
- (ख) ऐसी किसी स्थिति में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति जारी रहने की संभावना है।
- (ग) यह वास्तविक क्षति ई यू से संबद्ध वस्तु के सतत पाटित आयातों के कारण होने की संभावना है।

ठ. कारणात्मक संबंध

73. प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांच में कारणात्मक संबंध की महत्ता और प्रासंगिकता से संबंधित अनुरोधों की जांच की है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि अधिनियम की धारा 9 (5) के अंतर्गत प्राधिकारी के लिए पाटन एवं क्षति की संभावना तथा शुल्क जारी रखने की जरूरत की जांच करना अपेक्षित होता है भले ही समीक्षा जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात किया गया हो अथवा नहीं। तथापि, इस बात की जांच की गई थी कि क्या पाटनरोधी नियमों में सूचीबद्ध अन्य मापदंडों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इस संबंध में निम्नानुसार नोट किया जाता है:

अन्य देशों से मात्रा तथा कीमत

74. आयात के आंकड़ों से यह नोट किया हाता है कि संबद्ध वस्तु का आयात कई अन्य देशों से किया गया है और उनकी मात्रा न्यूनतम सीमा से कम रही है। चीन जन.गण., जापान, कोरिया गण., मलेशिया, रस, ताईवान और थाईलैंड से संबद्ध वस्तु के आयात मात्रा में अधिक रहे हैं और इनमें संचयी रूप में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि प्रदर्शित हुई है। अतः इस बात की जांच की गई थी कि इन स्रोतों से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने इन स्रोतों से संबद्ध वस्तु के पाटन का आरोप लगाते हुए एक आवेदन पहले ही दायर कर दिया है और उसकी विधिवत जांच के उपरांत प्राधिकारी ने इस बात की जांच करने के लिए कि क्या इन देशों से संबद्ध वस्तु के स्पष्ट पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, 3 नवंबर, 2009 की अधिसूचना के तहत पाटनरोधी जांच शुरू की है। चूंकि इन देशों से हुए आयात स्पष्टतः पाटित कीमतों पर हुए हैं अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस प्रकार के प्रत्यक्ष पाटित आयातों से हुई क्षति को वर्तमान मामले के लिए अलग करना अपेक्षित नहीं है। अन्य स्रोतों से हुए आयात मात्रात्मक रूप में न्यूनतम हैं और इसलिए इनसे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है।

मांग में कमी और/अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन

75. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में 35.78% की वृद्धि हुई है। खपत की पद्धति में हुए किसी परिवर्तन का भी कोई संकेत नहीं है।

विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा;

76. संबद्ध वस्तु का आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं है और यह देश में मुक्त रूप से आयात योग्य है। घरेलू उत्पादक एक दूसरे के बीच प्रतिस्पर्धा करते हैं और साथ ही साथ संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। घरेलू उद्योग की कीमत संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत से अत्यधिक प्रभावित होती है। इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह संकेत देने के लिए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में कोई अंतर आया है।

प्रौद्योगिकी विकास

77. किसी भी पक्षकार ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के कारण के रूप में प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित कोई मुद्दा नहीं उठाया है और न ही प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई खास विकास प्रतीत होता है जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति का प्रमुख कारण बन सकता हो ।

निर्यात निष्पादन

78. संबद्ध वस्तु का कोई निर्यात नहीं हुआ है । प्राधिकारी ने घरेलू प्रचालनों के संबंध में लाभप्रदता तथा कीमत संबंधी अन्य मापदंडों पर भी विचार किया है ।

उत्पादकता

79. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट प्रदर्शित हुई है । यद्यपि घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि लाभप्रदता में गिरावट पाटन के कारण उत्पादन में आई गिरावट के कारण आई है और इस प्रकार की क्षति को अलग करना अपेक्षित नहीं है । तथापि, प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि यदि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता समान रही होती तो क्या घरेलू उद्योग से संबंधित सूचना से क्षति का पता चल सकता था । यह नोट किया गया कि कम उत्पादकता का प्रभाव उत्पादन लागत और परिणामतः लाभ/हानि, निवेश पर आय एवं नकद प्रवाह पर पड़ा है । प्राधिकारी ने उत्पादकता में आई किसी गिरावट पर विचार करते हुए लाभ, आर आई आई एवं नकद प्रवाह के स्तरों का आकलन किया है और यह पाया है कि घरेलू उद्योग की स्थिति काफी अलग नहीं रही है ।

80. इस प्रकार प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य सूचीबद्ध ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है ।

81. अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध क्षेत्र से पाटित आयातों के कारण क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है । इसकी पुष्टि निम्नलिखित से होती है:

(क) विचाराधीन उत्पाद के आयातों में भारी वृद्धि हुई है । इसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग ने अपना बाजार हिस्सा गंवाया है ।

(ख) घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम कीमत पर भारत में पाटित आयातित संबद्ध वस्तु की मौजूदगी के कारण उसे बिक्री मात्रा का नुकसान हुआ है ।

(ग) आयातों के बाजार हिस्से में अत्यधिक वृद्धि हुई है और उसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है ।

(घ) बिक्री मात्रा में गिरावट संबद्ध क्षेत्र से पाटित आयातों के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप आई है ।

(ङ) आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हो रही है ।

(च) आयातों से घरेलू कीमतों में हास हो रहा है । घरेलू उद्योग कम कीमत पर आयातित वस्तु की उपलब्धता के कारण अपनी उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमत को बढ़ाने से वंचित हुआ है ।

(छ) लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय तथा नकद लाभ में गिरावट स्पष्टतः पाटित आयातों के कारण आई है ।

(ज) आयात अभी भी पाटित कीमतों पर जारी हैं और पाटित आयातों की मात्रा उच्च स्तर पर बनी हुई है। स्पष्टतः मूल जांच के समय विद्यमान परिस्थितियां आज की तारीख को भी उसी रूप में मौजूद हैं। परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे यह भी पता चलता है कि शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन संभवतः उच्च स्तर पर जारी रहेगा।

(झ) घरेलू उद्योग की वृद्धि कई मापदंडों के संबंध में ऋणात्मक हो गई है।

82. अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पाटनरोधी नियामावली के अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 के भीतर संबद्ध देश के मूल के या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ड. पाटन एवं क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना

83. प्राधिकारी नोट करते हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद संबद्ध क्षेत्र से पाटन जारी है और ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क लागू न रहने की स्थिति में संबद्ध क्षेत्र से संबद्ध वस्तु के पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति जारी रहने की संभावना है। अतः पाटन एवं क्षति के जारी रहने की संभावना की आगे और जांच अपेक्षित नहीं है।

ढ. निष्कर्ष

84. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदत्त सूचना और किए गए अनुरोधों तथा उपर्युक्त जांच परिणामों में दर्ज प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा पाटन एवं परिणामी क्षति के जारी रहने और पाटन एवं क्षति के जारी रहने की संभावना के बारे में किए गए उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

- i. भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रही है और संबद्ध क्षेत्र से आयातित संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन पर्याप्त तथा निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है। मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पाटित कीमतों पर भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात जारी है।
- ii. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद घरेलू उद्योग की स्थिति आगे और खराब हुई है। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने और उसमें वृद्धि होने की संभावना है।
- iii. घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट संबद्ध क्षेत्र से हुए पाटित आयातों के कारण आई है।
- iv. पाटनरोधी शुल्क का वर्तमान स्तर सतत पाटन एवं घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति को समाप्त करने के लिए अपर्याप्त है और इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क की अवधि को बढ़ाना और उसकी राशि में संशोधन करना अपेक्षित है।

४. सिफारिशें

85. इस आशय का निष्कर्ष निकालने के बाद कि उत्पाद का निर्यात पाटित कीमतों पर जारी है, वर्तमान पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन से लागू पाटनरोधी शुल्क में संशोधन करने की जरूरत की पुष्टि होती है, घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है और शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन तथा परिणामी क्षति जारी रहने की संभावना है। अतः प्राधिकारी का मत यह है कि इस उपाय की अवधि त्रिवेदी बढ़ाना अपेक्षित है तथा पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में निम्नलिखित शुल्क तालिका में किए गए उल्लेखानुसार संबद्ध क्षेत्र से हुए आयातों के संबंध में संशोधन करना अपेक्षित है।

86. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन जो भी कम हो, के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार संबद्ध क्षेत्र के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिए जाने की स्थिति में निम्नलिखित तालिका के कालम 8 में उल्लिखित राशि के अनुसार पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्षक/ उप-शीर्षक	वस्तु विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	39042210	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	यूरोपीय यूनियन	कोई	कोई	कोई	267.38	प्रति मी.ट.	अम.डॉ.
2	39042210	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन	कोई	यूरोपीय यूनियन	कोई	कोई	267.38	प्रति मी.ट.	अम.डॉ.

87. इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथानिर्धारित आकलनीय मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3, 8 1, 9 तथा 9 के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर समस्त सीमाशुल्क शामिल होंगे।

88. इस आदेश के खिलाफ कोई अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2010

Subject : Sunset Review Investigation of Anti-dumping duty imposed on imports of PVC Paste Resin originating in or exported from European Union—Final Findings.

No.15/27/2008-DGAD. — Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules), the definitive anti-dumping duty was originally imposed vide notification No.104/2004-Customs, dated the 7th October 2004 on import of PVC Paste Resin (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from European Union (hereinafter referred to as the subject country/territory).

B. BACKGROUND

2. And whereas, in view of the order of the Hon'ble Delhi High court in the matter of Indian Metal and Ferro Alloys Ltd V/s Designated Authority, Writ Petition (Civil) No. 16893 of 2006 and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of AD Rules, the Authority issued a public notice dated 31st March 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the sunset review investigation to review the need for continued imposition of duties in force and to examine whether the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

3. And whereas, antidumping duty as notified vide Notification No. 104/2004 dated 7th October 2004 was extended up to 6th July 2010 vide Customs notification No. 115/2009 dated 6th October 2009 in terms of Section 9(A)(5) of the Act.

C. PROCEDURE

4. In this proceeding, the procedure described herein-below has been followed:

- i. The Office of Delegation of European Union in India was informed about the initiation of the investigation, in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules.
- ii. The Designated Authority sent copies of initiation notification dated 31st March 2009 to the Office of Delegation of European Union in India, known exporters

from the subject territory, known importers and other interested parties, and the domestic industry, as per the information available with it. Parties to this investigation were requested to file the questionnaires' responses and make their views known in writing within the prescribed time limit. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to the Office of Delegation of European Union in India along with a list of known exporters / producers with a request to advise the exporters/ producers from the subject territory to respond to the questionnaires within the prescribed time.

iii. Questionnaires were sent to the following known exporters from the subject territory in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules to elicit relevant information:

S.N.	Company's Name
1.	Vestolit GmbH & Co KG, <i>Denmark</i>
2.	EVC Business Centre, <i>UK</i>
3.	Vestolit GmbH & Co KG, Postfach, <i>Germany</i>
4.	Solvin SA, Brussels, <i>Belgium</i>
5.	Vinnolit, Ismaning, <i>Germany</i>
6.	Alscondel, Barcelona

None of the exporters/producers from the subject territory responded to the questionnaires in response to the above notification.

iv. Questionnaires were sent to the following known importers, users and associations of the subject goods in India for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

S.N.	Company's Name
1.	Akzo Nobel Coatings India Pvt. Limited, Karnataka
2.	Alleppey Co Ltd., Kerala
3.	Anabond Essex India P Ltd, Chennai.
4.	Creative World, Mumbai
5.	D C Mills (P) Ltd, Kerala
6.	DRG Leather P Ltd, Kerala
7.	Eftec Shroff India Limited, Mumbai
8.	Fenner Conveyor Belting Pvt Ltd, Tamil Nadu
9.	Fenoplast Ltd, Andhra Pradesh
10.	Halol Leather Cloth Ltd, Mumbai
11.	Henkel Teroson India (P)Ltd., Haryana
12.	Hindusthan Seals Ltd, Calcutta
13.	International Conveyore Ltd., Aurangabad
14.	Jasch Industries Ltd., New Delhi
15.	Kerafibertex International P Ltd., Cochin
16.	Kerala Balers Ltd, Kerala

17.	Mayur Uniquoters Ltd, Jaipur
18.	Oswal Cable Products, New Delhi
19.	Phiroze Sethna P Ltd., Mumbai
20.	Polmann India Ltd., Mumbai
21.	Polynova Industries Ltd., Goa
22.	Premier Polyfilm Ltd., New Delhi
23.	Roto Screentech Ltd., Rajkot
24.	Shivam Textiles, New Delhi
25.	Siel Tizit Ltd, Calcutta
26.	Sneha Vinyl Products P Ltd., Andhra Pardesh
27.	SRF Limited, Tamilnadu
28.	Texon Industries P Ltd., Chennai

S.N.	Association's Name
1.	Leather Cloth and Plastics Manufacturers Association (LCPMA), New Delhi

In response to the above notification, M/s Mayur Uniquoters limited and M/s Jasch Industries Ltd. filed their importer's questionnaire responses; whereas Leather Cloth and Plastics Manufacturers Association (LCPMA), an association of importers and users of the subject goods filed their submissions on the subject.

- v. In response to the initiation notification, M/s. Chemplast Sanmar Ltd., Chennai responded and filed their submissions along with information/data requesting for conducting the sunset review and, *inter alia*, sought extension of the anti dumping duties. The company submitted the information/data for undertaking the injury analysis. However, M/s Finolex Industries Ltd. did not respond to the initiation notification.
- vi. The imports data for the period of investigation and preceding three years was called from Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S).
- vii. The Authority made available non-confidential version of the information/data and evidence presented by the interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- viii. The Authority examined the information furnished by M/s. Chemplast Sanmar Ltd., Chennai to the extent possible on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) to analyze the injury suffered and to work out the cost of production, cost to make and sell the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- ix. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 25th February 2010. The parties which presented their views in the public hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The arguments made in the written submissions/rejoinders

received from the interested parties have been considered, wherever found relevant, in this finding.

- x. The period of investigation for the purpose of the present review is April 2008 – March 2009 (POI). However, injury analysis covered the periods April 2005–March 2006, April 2006–March 2007, April 2007–March 2008 and the POI.
- xi. In accordance with the Rule 16 of the AD Rules, the essential facts considered by the Authority were disclosed to the known interested parties. The comments received on the disclosure statement have been duly considered in these findings.
- xii. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xiii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these findings on the basis of the 'facts available'.
- xiv. *** In this notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the AD Rules.

D. Submissions of interested parties in response to the Disclosure Statement.

5. The following interested parties have responded to the Disclosure Statement:

1. M/s. Chemplast Sanmar Ltd., Chennai.
2. M/s. Mayur Uniquoters Limited, Jaipur; and
3. M/s. Leather Cloth & Plastics Manufacturers Association, New Delhi.

6. Submissions made by M/s Chemplast Sanmar Ltd

- The domestic industry has reiterated its previous submissions and has argued that the submissions made by opposing interested parties with regard to difference in suspension and paste PVC should be rejected.
- PVC paste Resin produced by the domestic industry is used both in top coat and foam coat. The company produces three grades of PVC Paste Resin, 120, 121 and 124. Leather cloth contains three layers and all three layers can be produced from 124 grade of petitioner product. Grade 120 is used in production of sealants etc and 121 is used where high strength is required viz. for leather cloth to be used for production of football etc. Therefore, the claim of opposing parties is incorrect. In brief, the domestic industry has reiterated their arguments on top coat and foam coat and has submitted that the claim of the interested parties on this account is without any basis.
- With regard to standing, petitioner submits that there are two producers of the product in the Indian market and the company account for a major proportion of total Indian production and the petitioner constitutes domestic industry within the meaning of the AD Rules.

7. Submissions made by M/s Mayur Uniquoters Limited, Jaipur

- It has been stated that they did not receive the copy of the Disclosure Statement in time and received it through letter from M/s. Leather Cloth & Plastics Manufacturers Association and hence desire the extension of time.
- It has been contended that the product manufactured and supplied by M/s. Chemplast Sanmar Ltd., Chennai to them and all the members of the Association are not PVC Resin (Emulsion Grade) but the PVC Resin.

8. Examination by the Authority

- The Authority notes that the Disclosure Statement was duly sent to all interested parties participating in the investigation including to M/s. Mayur Uniquoters Limited, Jaipur via speed post. Therefore, it is incorrect to state that the Disclosure Statement was not sent to M/s. Mayur Uniquoters Limited. The Authority further notes that due to time constraints to complete this investigation, it is not feasible to grant extension of time to any interested party at this late stage.
- The Authority notes that at the time of initiation of this investigation itself it was clarified that the ambit and scope of the investigation was PVC Paste Resin (Emulsion Grade). The Authority further notes that the scope of the investigation cannot be enhanced in a sunset review investigation.

9. Submissions made by M/s. Leather Cloth & Plastics Manufacturers Association, New Delhi

- It has been contended that the only difference between paste resin and suspension resin is their particle size. Otherwise, they are the same in their application, manufacturing, raw material cost and end products. PVC suspension resin is chemically the same as PVC paste resin, only their physical appearance is different.
- As regards *inter se* comparison of various grades of paste resin, it is incorrect to say that the molecular weight, air release property and theological behaviour of all the grades of paste resin are same. Different grades are meant for different applications and their variation is from zero to 400 dollars. They are meant for different products and different applications irrespective of suspension grade resin or paste grade resin.
- There is a monopoly in manufacturing of PVC paste resin.
- They import PVC Paste Resin of superior quality and they are forced to import minimum of 30% of premium quality of PVC paste resin for its top coat requirement.
- Imports are only 6% of Indian consumption and therefore, the finding that the dumped imports from EU are significantly undercutting the prices of domestic industries is wrong.

10. Examination by the Authority

- As regards the difference between paste resin and suspension resin, the Authority notes that except reiterating this submission, the association has not submitted any evidence to substantiate their claim. It is further noted that they have sought

extension of time of about two months for collection of relevant data to make a further effective representation before the Authority. The Authority, however, notes that this is a too belated request in the current proceedings. The Authority is required to complete the investigation within the time limits prescribed under the AD Rules. No evidence substantiating their claim has been provided by the Association till date. Moreover, acceptance of new facts after the issuance of the disclosure statement may require grant of opportunity to other interested parties as well. Thus, the Authority considers that due to time constraints to complete this investigation, it is not feasible to grant extension of time to any interested party.

- As regards submissions relating to inter se comparison of various grades of paste resin, no evidence substantiating their claim has been provided by the Association till date.
- The Authority notes that M/s Chemplast Sanmar Limited is not the sole producer of the subject goods. Besides, the users may have access to imported product as well but not at the dumped prices, as the objective of the anti-dumping duty is not to thwart the imports but to ensure that the dumped imports do not cause injury to the domestic industry.
- The quality claim too has not been substantiated by the Association.
- As regards the issue that imports are only 6% of Indian consumption; the Authority notes that in a sunset review investigation, the Authority may reach a conclusion of likelihood of dumping and consequent injury even though the subject goods may have not been imported during the POI. In any case, the imports are significantly above the volume de-minimis level and are causing material injury to the domestic industry as would be noted from the injury analysis.

E. Product under Consideration and Like Article

E.1. Submissions made by M/s. Chemplast Sanmar Ltd., Chennai

11. M/s. Chemplast Sanmar Ltd., Chennai has made the following submissions:

- (i) The product under investigation in the original investigation and present review is Poly Vinyl Chloride Paste Resin also known as Poly Vinyl Chloride Resin (Emulsion grade) or PVC Paste Resin. It is produced from Vinyl Chloride Monomer (VCM) and VCM is produced from EDC, which in turn require chlorine as major raw material. It is produced and sold in white/off white powder. It is produced in a number of grades, which differ in "K values". Various grades are technically and commercially substitutable. It is used in the artificial leather (Rexene), coated fabrics, Tarpaulins, conveyor belting, Toys, Automotive sealant and adhesives etc.
- (ii) It is classified under subheading no 39042210 in the Customs Tariff Act though the imports have been cleared in a number of classifications.
- (iii) The Poly Vinyl Chloride (suspension grade) classified under 39042110 is different from the subject goods and is not included under product under consideration.
- (iv) The goods produced by the domestic industry are like article to the imported product. There is no known difference in PVC Paste Resin produced by the Indian industry and subject goods exported from subject country. The issue of product under consideration and like article was examined in detail by the Designated Authority in the original investigations and it has been held that the imported and domestic products are like article.

(v) Present review investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as has been defined in the previous investigations.

E.2. Views of the importers, consumers, exporters and other interested parties

12. The following submissions have been made by Leather Cloth and Plastics Manufacturers Association (India):

- (i) PVC Paste Resin is of two types, (A) Suspension Grade and (B) Emulsion /Paste Grade. The only difference between Emulsion & Suspension Grade is in respect of particle size.
- (ii) Chemplast Sanmar is manufacturing both Suspension and Emulsion types of PVC Resin, but has applied for imposition of anti dumping duty only on Paste / Emulsion Grade, which is relatively small proportion of its total PVC Resin production.
- (iii) The domestic industry manufactures only one grade i.e.124 which is used in the production of PVC Leather Cloth.
- (iv) Chemplast's PVC Paste Resin is utilized by the members only for the Foam Coat whereas the consumers import PVC Paste Resin of superior quality, which is used for top coat. The requirement of PVC Paste Resin for top coat and foam coat is in the ratio of 30:70. Therefore, industry is forced to import minimum 30% of its requirement of top coat resin.
- (v) Historically the difference in the prices of PVC Suspension and PVC Paste Grade is about Rs 10-12 per Kg. However today the price of PVC Suspension Grade is about Rs 58-60 per kg, while that of Emulsion Grade is Rs 80-85 Per kg, which has resulted in abnormal price differential of Rs 25-27 per kg.
- (vi) Imposition of Anti Dumping duty on PVC Paste Resin will further distort the price structure of PVC Paste Resin vis-à-vis PVC Suspension Resin. The additional cost involved in the manufacture of PVC Paste resin as compared with PVC Suspension grade is only about Rs 6-7 per kg.

13. No other interested party has filed any submissions in the instant matter.

E.3. Examination by the Authority

14. The Authority notes that the product under consideration in the original case was "Poly Vinyl Chloride Paste Resin" also called as Emulsion PVC Resin and also referred to as PVC Paste Resin. The product under consideration (also referred to as the subject goods) remains the same for the purposes of the present Sunset Review investigation.

15. The PVC Paste Resin is produced from Vinyl Chloride Monomer (VCM). VCM is produced using EDC, which in turn requires chlorine as one of the major products. The subject goods is produced and sold in the form of white/off-white powder. The properties of the product are described in terms of K value, inherent viscosity, particle size retention, heat loss, initial BFB etc. All grades of the subject goods are subject matter of present investigation and are within the scope of product under consideration. Common applications of PVC Paste Resin are artificial leather, Rexene, coated fabrics, tarpaulins, conveyer beltings, toys, automotive sealant, adhesives etc. The subject goods are processed at consumer end, by mixing liquid plasticizers like DOP to form free flowing mixtures.

16. The subject goods are classified under subheading no 39042210 in the Customs Tariff Act. M/s. Chemplast Sanmar Ltd. has claimed that the imports have been cleared under a number of classifications as well.
17. With regard to Poly Vinyl Chloride (suspension grade) classified under 39042110, the Authority notes that the difference and similarities between suspension grade PVC and paste grade PVC were examined by the Authority in detail at the time of original investigation. No fresh evidence has been provided by any interested party warranting the review of the conclusion earlier made by the Authority in this regard. In response to the disclosure statement, Leather Cloth and Plastics Manufacturers Association have sought extension of time to substantiate their contentions. The Authority, however, notes that this is a too belated request in the current proceedings. The Authority is required to complete the investigation within the time limits prescribed under the AD Rules. No evidence substantiating their claim has been provided by the Association. Moreover, acceptance of new facts after the issuance of the disclosure statement may require granting of opportunity to the other interested parties and verification of information/evidence provided by the interested parties. It is also relevant to note that the present investigation is in the nature of sunset review investigation and the interested parties had made detailed submissions at the time of original investigation, claiming suspension and paste PVC resin as a different product. The Authority, however, did not find the two as one article. It is also relevant to note that the Authority had earlier conducted investigation into dumping of PVC suspension resin, wherein the scope was restricted to PVC suspension resin only. In any case, the Association could have submitted the relevant evidence to support their contentions during the year long process of investigation. As the claims of the Association remain unsubstantiated, the Authority is of the view that PVC suspension grade resin is a different product and is not within the scope of the product under consideration.
18. With regard to the argument that the paste PVC resin can be used for top coat and foam coat and that the domestic industry produces only one type of paste PVC resin; the Authority notes that while advancing this argument, the interested parties have provided no evidence to substantiate their claim. The interested parties have not established that the different grades of PVC paste resin or PVC paste resin produced by the domestic industry and imported from the subject territory are not comparable on the basis of physical and chemical characteristics, manufacturing process, functions and uses, product specifications, pricing, customs classification, etc. The domestic industry on the contrary has contended that the same grade produced and supplied by them is used by these consumers for both top and foam coat. The domestic industry has further contended that in fact there are three layers of leather cloth, top coat, base coat and form coat and all the three coats are prepared by the consumers using the same grade of PVC paste resin supplied by the domestic industry. Besides this, it has also been contended by the interested parties that the domestic industry does not supply grades comparable to the imported grades but have not substantiated their claim. It is noted in this regard that similar contentions were made at the time of original investigation as well but the Authority did not find sufficient justification to exclude the grades from the scope of the investigation.
19. The Authority notes that the present investigation is in the nature of sunset review investigation and therefore the scope of the product under consideration would

normally remain the same as was in the original investigation, unless an interested party establishes the need to restrict the scope of the product under consideration. The Authority notes that though product PVC paste resin has a number of grades and sub-types, all of whom have similar physical and chemical characteristics and end uses; even though specifications in terms of K values and other parameters are controlled by the manufacturers to produce these grades. No material evidence has been placed by any interested party to establish that these different grades are not like articles to each other. The Authority also notes that the submission of the interested parties is based on the contention that the domestic industry does not produce some grades. It has, however, not been established that these grades are not alike to the grades produced in respect of their physical and chemical characteristics and technical and commercial substitutability.

20. The Authority thus notes that PVC resin of different grades are being imported into India and the interested parties have not placed any evidence on record to establish that the different grades of PVC resins are different products and are not technically and commercially substitutable. Therefore, the Authority does not find any merit in the contentions of the interested parties for exclusion of these grades. Thus, the Authority holds that the goods produced by the domestic industry are like articles to the imported subject goods.

F. Standing and scope of the Domestic Industry

F.1. Submissions made by M/s. Chemplast Sanmar Ltd., Chennai

21. M/s Chemplast Sanmar Ltd. is a major producer of the subject goods in India, as it commands 78.97 % of the Indian production. The company satisfies the requirement of 'standing' and constitutes 'domestic industry' within the meaning of the AD Rules.

F.2. Submissions made by the importers, consumers, exporters and other interested parties

22. The submissions have been filed by Leather Cloth and Plastics Manufacturers Association (LCMPA) (India). No other interested party has filed any submissions. None of the interested parties have made any submission in respect of 'domestic industry'.

23. M/s LCMPA (India) has, *inter alia*, contended that there is only one producer of subject goods in India.

F.3. Examination by the Authority

24. At the time of the initiation of this review investigation, Rule 2(b) of the AD Rules read as follows:-

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are

themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers only":

However, the Rule 2(b) of the AD Rules has recently been amended to read as:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers only"

25. In the present review investigation, M/s Chemplast Sanmar Ltd. has responded to the initiation notification. The Authority notes that M/s Chemplast Sanmar Ltd. is a major producer of the subject goods in India as it accounts for 78.97% of total Indian production. Therefore, M/s Chemplast Sanmar Ltd satisfies the requirement of 'standing' and constitutes 'domestic industry' within the meaning of the AD Rules.

G. Dumping Determination

Normal Value

G.1. Submissions made by the Domestic Industry

26. It has been contended by the domestic industry that the producers from EU are dumping the subject goods in India. Efforts were made by them to obtain information about the prices of PVC Paste/Emulsion Resin prevailing in the domestic market in European Union; but no reasonable, authentic and accurate information could be obtained by them about the actual transaction-wise selling price of the subject goods (between a producer and wholesaler dealer/distributor) in their domestic market.

27. Efforts were also made by them to trace the prices of the subject goods in published journals. "Vinyl Chloride" from Harriman Chemsult Limited is an internationally acknowledged, widely relied upon authentic journal in this trade and that they have been able to get information about the prices in domestic market of subject country based on this journal.

28. In view of the same, the Normal value in subject territory has been estimated on the basis of the prices reported by this journal.

G.2. Submissions made by the Exporters/Importers/Other interested parties

29. None of the exporter or producer has filed the questionnaire response in the form and manner prescribed. M/s Chemplast Sanmar Ltd has, *inter alia*, contended that the dumping margin should be based on the domestic selling prices in EU; while the Leather Cloth and Plastics Manufacturers Association has submitted that it would not be appropriate to determine the Normal value based on the prices published in journal "Vinyl Chloride" from Harriman Chemsult Limited.

G.3. Examination by the Authority

30. None of the exporters/producers in EU has cooperated with the Authority in this investigation. In view of non-cooperation by the exporters/producers in EU, the Authority has considered information and facts available on record. The Authority notes the claim of the domestic industry that efforts were made by them to obtain information about the prices of subject goods prevailing in the domestic market of EU, but no reasonable, authentic and accurate information could be obtained by them about the actual transaction-selling price of subject goods in their domestic market.

In view of the non-co-operation from the exporters/producers in EU, the Authority has constructed the Normal value. For this purpose, the Authority notes that though the prices of the subject goods are regularly published in journal, namely "Vinyl Chloride", which is published by Harriman Chemsult Limited but some interested parties have contended that prices of the subject goods published in the journal may not be reliable because of variations in grades of the PUC and their corresponding prices. In any case, considering non-co-operation of the EU exporters/producers in the instant matter, the Authority has little choice except resorting to construction method of determination of the Normal Value. Therefore, the Authority has constructed the Normal value for EU considering international prices of major raw materials, consumption factor of domestic industry and conversion cost of domestic industry and the Normal value so determined works out as US\$ ***per MT.

H.4. Export Price

31. The Authority notes that none of the exporters / producers from EU has cooperated with the Authority in this investigation. In view of non-cooperation by the exporters / producers in EU, the Authority has considered information and facts available on record.

32. In view of non-cooperation by the foreign exporters / producers, the Authority considered whether import statistics provided by IBIS and DGCI&S could be used to determine the Export price of the subject goods during the relevant period. Thus, the Authority has determined weighted average import price for the product under consideration.

33. The domestic industry has claimed volume, value and import price on the basis of information provided by IBIS. The Authority also called for the data from DGCI&S; the analysis of which revealed that the volume of imports reported by the DGCI&S during the POI were substantially lower than the volume of imports reported by the IBIS. The Authority, therefore, corroborated the two data and compared first customs classification wise and thereafter customs port wise volume and value of imports reported in the two sources.

34. It is seen that there are significant differences in the volumes reported in the two sources. A significant difference is observed in import data reported at Cochin port. Further, analysis of classification wise imports shows that significant differences have been reported in other classifications (in particular under 3904 2110).

35. In view of the same, the Authority has adopted import data reported by IBIS in order to determine volume, value and import price of imports for the purpose of present determination as volume is much higher in the IBIS data, while the price per unit is almost similar in both the sources.

36. The prices reported in the IBIS are CIF import prices. In view of non cooperation from the EU producers/exporters, the Authority has made price adjustments on the basis of best available information in order to arrive at ex-factory export price to India. Price adjustments have therefore been made with regard to ocean & inland freight, port handling, marine insurance. The Authority has determined the ex-factory export price of subject goods for all exporters or producers from European Union as follows:

Particulars	Unit	European Union
Import volume	MT	3,374
Import value	Rs. Lacs	1,766.44
CIF import price	Rs./MT.	52,354
Exchange rate	Rs./US\$	45.72
CIF export price in US\$	US\$/MT	1,145.08
Price adjustments (total)	US\$/MT	***
Ex-factory export price	US\$/MT	***

I. Dumping Margin

37. Since none of the exporters /producers from EU has responded to the Authority in this investigation, the Authority notes that individual dumping margins for the exporters/producers cannot be determined. The Authority has therefore determined weighted average dumping margin for all producers/exporters of the subject goods from EU. On the basis of normal values and net export prices determined as explained above at ex-factory level; the dumping margin during POI for all exporters/producers from the subject territory has been determined, as detailed below:

	Units	European Union
Normal Value	US\$/MT	***
Export Price	US\$/MT	***
Dumping Margin Range	US\$/MT	300-320
Dumping Margin	%	27.73%

J. Continuation or recurrence of dumping:

38. While there is no response from any of the EU producers/exporters, the domestic industry has submitted the following:

- (a) EU producers/exporters have not responded to the Authority and have not provided information in the form and manner prescribed.
- (b) The authority has prescribed specific additional requirements for sunset review. The EU producers/exporters have not responded to this questionnaire as well.
- (c) Any other party opposing extension of ADD also has not provided any information to the Authority in this regard.
- (d) There is a significant dumping margin from European Union. Dumping from European Union has not ceased in spite of anti-dumping duty being in existence.
- (e) The product under consideration continues to be exported in significant volumes and the dumping margin in respect of current exports is quite significant.
- (f) The producers in Europe are exporting the product to several countries. Imports from EU have increased after imposition of anti-dumping duties.
- (g) The producers in EU are understood to have significant surplus capacities.
- (h) While producers normally use production facilities between suspension and paste PVC on dedicated basis, it is possible for the producers to divert suspension PVC capacities to production of PVC Paste Resin and vice versa with minimal efforts. Thus possibilities of suspension PVC capacities being utilized for PVC Paste Resin are not ruled out.

39. In view of the above, the Authority considers that dumping of the subject goods is likely to continue in the event of cessation of the Anti-dumping measure in force.

K. Injury

K.1. Submissions made by the Domestic Industry

40. The submissions made by the domestic industry with regard to injury and causal link, in brief, are as follows:

- (a) Product under consideration continues to be exported to India from the subject territory and other major countries at dumped prices;
- (b) Dumping has continued inspite of existing anti-dumping duties;
- (c) Domestic industry has not been able to improve its performance to the extent it could have;
- (d) Imports from subject territory and other dumping countries have increased in relation to total imports, production and consumption in India.
- (e) Performance of the domestic industry has deteriorated in terms of production, capacity utilization, sales values & volume, profits, return on investments, cash flow, and market share.
- (f) Capacity utilization of the domestic industry continued to remain sub-optimal in spite of existence of significant demand.

- (g) Continued dumped imports are at prices significantly lower than the cost of production of domestic industry that has resulted in suppression of the domestic prices of the subject goods.
- (h) The domestic industry has suffered continued material injury.
- (i) The current level of anti-dumping duties are grossly inadequate to prevent injurious dumping because of increase in raw material prices;
- (j) Anti-dumping duty is required to be extended, considering the dumping margin and injury margin in the present investigation.

K.2. Submissions of other interested parties

41. Submissions have been filed by M/s Mayur Uniquoters limited (in response to the Disclosure statement) and Leather Cloth and Plastics Manufacturers Association. No other interested party has made any submissions. There is no response from any producer/exporter from EU. Nor has any arguments been advanced on any aspect of the present investigation, including on injury & causal link:

42. M/s Leather Cloth and Plastics Manufacturers Association (India) has, *inter alia*, contended that:

- There have been frequent break downs / stoppage in the PVC Plant of Chemplast Sanmar, particularly during 2008-09 and in the current year, as a result of which Chemplast has not been able to meet the full demand of PVC Paste Resin in the Country.
- Prevailing international Prices of PVC paste resin is in the range of USD 1400 to 1500 ton and the landed price works out to Rs 85 – 87 per kg. as against prevailing domestic price of Rs 79-80 of Chemplast. No Imports have been made from European Union in the last 2-3 year below the prices of Chemplast Sanmar.
- PVC Paste resin constitutes almost 40% of cost of raw material for the manufacturing of PVC coated fabric. There is already large scale import of PVC Coated Fabric from China, Taiwan & Korea. If anti dumping duty is levied on PVC paste resin, the manufacturers of PVC Coated Fabric will not survive. The levy of Anti Dumping duty on PVC Paste Resin will make domestic small scale PVC Coated Fabric industry uncompetitive vis-à-vis imports and most of the units will be forced to close down. PVC processing units are mostly in small scale sector providing employment to more than one lakh workers directly & indirectly spread all over the Country.

K.3. Examination by the Authority

43. M/s Leather Cloth and Plastics Manufacturers Association (India) have, *inter alia*, argued that M/s Chemplast had frequent breakdown or plant stoppages, particularly in 2008-09, as a result of which the company has not been able to meet the demand. The Authority, for this purpose, examined month-wise production of M/s Chemplast during 2008-09 and compared the same with the volume of imports during the period. It is seen that the company has produced the goods in all the months during the POI. Apparently, the volume of imports bears no correlation with the trends in production of the company. Further, the volume of imports is significantly higher than the decline in the volume of production of the company. Thus, the claim that the imports were necessitated due to frequent breakdown or plant stoppages has not been substantiated.

Month	Production in MT	Production Indexed	Imports in India in MT
April 08	***	100	1078
May 08	***	83	2117
June 08	***	79	1934
July 08	***	85	2482
Aug 08	***	74	5382
Sept 08	***	68	1761
Oct 08	***	89	621
Nov 08	***	88	664
Dec 08	***	85	1221
Jan 09	***	90	1561
Feb 09	***	76	2859
Mar 09	***	89	1594

44. Submissions made by interested parties in response to the Disclosure statement

M/s Chemplast Sanmar Ltd. and Leather Cloth and Plastics Manufacturers Association (India) have made the following submissions in response to the Disclosure statement:

45. Submissions made by M/s Chemplast Sanmar Ltd

- Decisions of the CESTAT have been referred by the domestic industry in support of their claim of injury and likelihood thereof.
- The anti dumping duty should be in the form of fixed quantum. The previous form of duty was neither appropriate, nor was able to prevent dumping causing injury to the domestic industry.
- The anti dumping duty should be expressed in US\$.

46. Submissions made by Leather Cloth and Plastics Manufacturers Association (India)

- In order to assess the cost of production of paste resin, the cost of production of suspension resin should also be taken into account from the data of the domestic industry because the raw material is 100% the same.
- Decline in profitability of domestic manufacturers can be on account of many reasons including inefficient use of production facilities.
- The apparent impression that the productivity of domestic industry has shown decline, is quite deceptive. The fact of the matter is that Chemplast can make both

suspension resin and paste resin and they can easily switch over from one to another. Therefore, one must have a look at the productivity of both suspension resin and paste resin together to get a realistic picture.

- They have sought extension of time of about two months for collection of relevant data to make a further effective representation before the Authority.

Examination by the Authority

47. The Authority has taken note of the arguments on injury examination and addressed the issues raised at appropriate places. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and the arguments of the interested parties.

48. Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

49. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows.

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment wages growth, ability to raise capital investments."

50. For the purpose of assessing the 'injury', the Authority has examined the volume and prices effects of imports of the subject goods from EU on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal link between dumping and injury, if any.

51. The Authority also notes that an anti-dumping application was filed by the domestic industry alleging dumping of the subject goods by the producers in China PR, Japan, Korea RP, Malaysia, Russia, Taiwan and Thailand; and that on being *prima facie* satisfied, the Authority initiated the anti dumping investigations vide notification dated 3rd November 2009 concerning the subject goods originating in or exported from these countries.

K.3.1. Volume effect

a) Assessment of Demand

52. For the purpose of assessment of the domestic consumption/demand of the subject goods, the sales volume of the domestic industry and other Indian producer have been added to the total imports into India, which has been summarized as under:

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)
Imports from Subject country	MT	840	891	292	3,374
Imports from other countries	MT	3,927	4,158	6,337	19,900
Total imports	MT	4,767	5,049	6,629	23,274
Sale of domestic industry	MT	30,733	29,184	27,664	23,269
Sales of other Indian Industry	MT	3,195	4,891	5,402	5,997
Demand	MT	38,695	39,124	39,695	52,540

The Authority notes that the demand has shown a positive trend and increased significantly in the period of investigation as compared to the base year. The growth in demand during the period of investigation over the base year was about 35.78 %.

b) Import volumes and market share

53. Annexure-II (ii) of the AD Rules provides that “while examining the volume of dumped imports, the Authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports either in absolute term or relative to production or consumption in India”. Thus, with regard to the volume of the dumped imports, it has been examined whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

54. The table below summarises the position with regard to import volumes and market share: -

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)
Imports from					
EU	MT	840	891	292	3,374
Imports from other countries under investigation	MT	3,636	3,740	6,313	19,020
Total Imports	MT	4,767	5,049	6,629	23,274
Indian Production	MT	33,703	34,636	32,442	29,439

Demand	MT	38,694	39,124	39,695	52,540
Subject imports in relation to					
Total Imports	%	17.62%	17.64%	4.40%	14.50%
Production	%	2.49%	2.57%	0.90%	11.46%
Consumption	%	2.17%	2.28%	0.73%	6.42%
Market share of domestic industry in demand	%	79.42%	74.59%	69.69%	44.29%

From the above, the Authority notes that:

- (i) The volume of dumped imports from EU which declined in 2007-08, increased significantly in the period of investigation.
- (ii) The increase in imports is inspite of existing anti dumping duties on imports from EU.
- (iii) Imports from subject territory have increased significantly in POI in relation to the total imports, production and consumption in India.
- (iv) As a result of the increase in imports, the share of the domestic industry has declined significantly.

K.3.2 Price effect of the dumped imports on the Domestic Industry

55. In order to ascertain the price effect of the imports of the subject goods from EU on the domestic industry, the Authority has examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In order to assess the extent of price undercutting, the Authority has compared net sales realization of the domestic industry with the landed price of imports. The net sales realization was arrived, after deducting all rebates and taxes. The landed value of imports was compared with net sales realization of the domestic industry, even after considering the anti-dumping measure in force. Landed price from EU including applicable customs duty and cess on custom duty is significantly below the net sales realization of the domestic industry. Further, in view of significant imports of the product from other countries, the Authority determined price undercutting in respect of these imports from third countries separately under investigations.

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)
Net Sales Realization	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	108	116
Antidumping duty Benchmark	Rs./MT	42,230	43,363	38,755	43,478
Average Landed Price from European Union	Rs./MT	42,475	50,243	54,307	55,077
Trend	Indexed	100	118	128	130
Price undercutting amount	Rs./MT	***	***	***	***

Price undercutting range	% Range	20-25	5-10	0-5	5-10
Average Landed price of imports from other countries separately under investigation	Rs./MT	54579	51951	49563	56453
Trend	Indexed	100	95	91	103
Price undercutting amount	Rs./MT	***	***	***	***
Price undercutting range	% Range	Negative	5-10	10-15	5-10

From the above, the Authority notes that:

- (i) The dumped imports from EU are significantly undercutting the prices of the domestic industry.
- (ii) As a result of significant difference in the price of the domestic industry and imports, the volume of imports has increased in the period of investigation.
- (iii) Though the landed price increased because of increase in CIF price, but the Authority notes that the increase in CIF price was lower than increase in the selling price of the domestic industry as would be seen from the following table.
- (iv) Imports from other countries separately under investigations are also significantly undercutting the prices of the domestic industry.

Price suppression/depression

56. In order to assess whether the imports from EU were suppressing the prices of the domestic industry, the Authority has compared the cost of production and net selling price of the domestic industry along with the landed price of imports over the injury period, which is given in the following table:

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)
Cost of Production	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	122	135
Net Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	108	116
Profit/Loss	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(171)	(352)	(442)
Average Landed price of imports from EU	Rs./MT	42,397	50,171	54,229	54,998
Trend	Indexed	100	118	128	130
Average Landed price of imports from other countries under investigations	Rs./MT	54,479	51,876	49,492	56,372
Trend	Indexed	100	95	91	103

The Authority notes that whereas both the cost of production and net selling price increased over the injury period, the increase in the net selling price were much lower

than the increase in the cost of production. Thus, the imports are significantly suppressing the prices of the domestic industry.

Economic Parameters relating to the Domestic Industry

57. Annexure II to the AD Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to determination of consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

Production, sales, capacity and capacity utilization

58. The production, sales, capacity & capacity utilization of the domestic industry has been as follows:

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)
Capacity	MT	34,080	34,080	34,080	34,080
Production	MT	30,789	29,117	27,584	23,249
Capacity utilization	%	90.34%	85.44%	80.94%	68.22%
Domestic sales	MT	30,733	29,184	27,664	23,269
Demand	MT	38,695	39,124	39,695	52,540
Production in % of demand	%	79.57%	74.42%	69.49%	44.25%
Sales in % of demand	%	79.42%	74.59%	69.69%	44.29%

It is noted that:

- The production, capacity utilization and sales of the domestic industry have declined in absolute term.
- The production, capacity utilization and sales of the domestic industry have declined in relation to demand/consumption of the product in India.
- The domestic industry has contended that production and sales of the domestic industry should have increased with the pace of increase in demand of the product in India. However, the dumping of the product has led to decline in these parameters. The Authority notes that the domestic industry has not been able to improve its production to the extent of capacity or the increase in demand.

d) The production and sales of the domestic industry significantly declined in relation to demand of the product in India. Domestic industry is not able to utilize its production capacities.

Profitability

59. The cost of production, net sales realization & profit/loss of the domestic industry is shown below:

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
Cost of Production	Rs./MT	***	***	***	***
Net Sales Realization	Rs./MT	***	***	***	***
Profit/Loss	Rs./MT	***	***	***	***
PBT on Domestic Sales	Rs. Lacs	***	***	***	***
PBIT on Domestic Sales	Rs. Lacs	***	***	***	***

60. The Authority notes that performance of the domestic industry for subject goods has deteriorated over the injury period and the domestic industry is in significant losses. The Authority examined profitability by considering the trends in the cost of production and selling prices over the injury period. It is found that both the cost of production and the selling prices increased throughout the injury period. But the increase in cost of production is far more than increase in selling price. Consequently, profitability of the domestic industry suffered severely during the POI.

61. In view of continued losses being suffered by the domestic industry, the extent of which increased over the current injury period, the Authority examined the reasons for continued financial losses by the domestic industry, particularly when anti-dumping duties were earlier imposed on imports from EU. It is noted that the anti-dumping duties were earlier imposed in the form of benchmark price. The import prices of the subject goods after the imposition of anti-dumping duties have been significantly higher than the ADD benchmark that the imports would not have attracted anti-dumping duties. Further, the domestic industry provided evidence to show that the increase in import prices was not due to elimination of dumping, but the same was due to significant increase in the raw material costs. The domestic industry has submitted that in fact, the increase in the import price was significantly lower than the increase in the cost on account of raw materials and that the product continued to be imported at dumped prices in spite of imposition of anti-dumping duties because of the form of duties.

62. It is also noted that the product under consideration is being imported from a number of other countries. Further, import price from various sources are comparable in respect of significant import volumes. Imports from China PR, Japan, South Korea, Malaysia, Russia, Taiwan and Thailand are prima-facie at dumped prices, for which the Authority is separately conducting an anti-dumping investigation. It is noted that the landed price of imports throughout the injury period from various sources dumping the subject goods remained substantially lower than the selling price of the domestic

industry, thus causing continued price undercutting. Existence of significant price undercutting prevented the domestic industry from charging a price which would have permitted reasonable recovery of the cost of production. It is further noted that while the costs increased throughout the injury period and even though the selling prices also increased but the increase in the selling prices was far lower than increase in the cost of production.

The Authority notes that continued dumping of the product from the subject territory and other sources has apparently led to financial losses suffered by the domestic industry throughout the injury period.

Market share

63. Comparison of the sales of the domestic producers and imports from EU and various the other sources shows that although the demand for the product has shown positive trend, the market share of domestic industry has declined significantly over the injury period, with the increase in the share of subject imports from EU and other countries.

Market Share in Demand	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)
Subject Country – European Union	%	2.17%	2.28%	0.73%	6.42%
Other Countries	%	10.15%	10.63%	15.96%	37.88%
Domestic industry	%	79.43%	74.59%	69.69%	44.29%
Other domestic producer	%	8.25%	12.50%	13.62%	11.41%

Employment and Wages

64. Position with regard to employment, wages and productivity as follows:

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)
No. of Employees	Nos.	***	***	***	***
Wages	Rs.lacs	***	***	***	***
Productivity per day	MT/day	***	***	***	***
Productivity per employee	MT	***	***	***	***

The Authority notes that the productivity of the domestic industry declined with the decline in production. The decline in productivity has ultimately resulted in decline in performance of the domestic industry. However, the Authority notes that the domestic industry is a multi-product company and hence the employment by the domestic

industry and wages paid may not be a correct parameter to evaluate the injury in the instant matter.

Return on investments and cash flow

65. The Authority notes that return on investment and cash profits situation of the domestic industry deteriorated significantly over the injury period. Similar is the situation of cash profit as well.

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (POI)
ROI - GFA Basis	%	***	***	***	***
Trend	Index	(100)	(203)	(340)	(363)
ROI - NFA Basis	%	***	***	***	***
Trend	Index	(100)	(219)	(358)	(400)
Cash Profit	Rs.Lac	***	***	***	***
Trend	Index	(100)	(162)	(316)	(335)
Cash Flow	Rs.Lac	***	***	***	***
Trend	Index	(100)	(50)	(601)	(421)

Inventories

66. Inventories of the domestic industry have shown a declining trend.

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
Average Inventories	MT	***	***	***	***

It has been claimed by the domestic industry that average inventory of the domestic industry declined is a direct result of curtailment of the production by the domestic industry, in view of presence of dumped imports in the market.

Magnitude of Margin of Dumping

67. The Authority notes that the dumping margin from EU is quite significant. The significant dumping margin in the period of investigation is also indicative of likely future behaviour of the exporters from EU.

Growth

68. The Authority notes that while there has been a substantial growth in the import volume from the subject country; but the growth of domestic industry in terms of sales, production, and capacity utilization has been negative. The growth in cash profits, profits and return on investment has also been negative over the injury period.

Likelihood of continued dumping & injury

69. The following factors have been brought before the Authority for examination of likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry. The domestic industry has pleaded that in a sunset review, the Authority is required to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to arrive at a decision to continue or vary or remove the duty so as to offset dumping. The Authority notes that:

- (i) That the producers from EU are dumping the material in the Indian market. Though there is a significant increase in the raw material prices, the export price of the exporters has not shown proportionate increase apparently indicating absorption of the cost by the exporters.
- (ii) That the injury to the domestic industry is still continuing and in case the duties are discontinued the injury to the domestic industry is likely to increase.
- (iii) That the landed price of imports from EU is much lower than the fair selling price domestic industry ought to get.
- (iv) That volume of imports from European Union has increased in spite of the antidumping duty in existence.
- (v) That the domestic industry has claimed that the producers are holding significant surplus capacities and their domestic demand is significantly below the capacities created by them. The Authority notes that this claim has not been disputed by any other interested party.

Magnitude of Injury and Injury margin:-

70. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports from EU for determination of injury margin during the POI. Thus compared, the injury margin is worked out as under:

NIP	Rs./MT	***
Landed Price	Rs./MT	54,998
Injury Margin	Rs./MT	***
Injury Margin (%)	%	20-25%

Conclusions on injury

71. In view of the above, the Authority concludes that despite the existence of anti dumping duties, the dumped imports from EU have continued and not only its volumes have increased in absolute numbers but the volumes have increased in terms of its share in total consumption of the subject goods in India as well. Besides, the imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry in the market. Further, the imports caused significant price suppression as well. While, both the cost of production and the selling price increased, the increase in selling price was far lower than the increase in the cost of production. The performance of the domestic industry deteriorated in terms of production, domestic sales, capacity, utilization, profits, return on investment, cash flow, productivity. Thus, the Authority is of the

view that the domestic industry continues to suffer material injury in spite of the existing anti-dumping duties.

72. In view of the above, the Authority holds that:

- (a) The product under consideration is likely to continue to be exported to India from EU below its associated Normal value, if the anti-dumping duties are revoked or are allowed to cease.
- (b) The domestic industry is likely to continue to suffer material injury in such an event.
- (c) The material injury is likely to be caused by the continued dumped imports of the subject goods from EU.

L. Causal Link

73. The Authority has examined the submissions with regard to the significance and relevance of causal link in a sunset review investigation. It is important to note that under Section 9A(5) of the Act, the Authority is required to examine the likelihood of dumping and injury and the need for continuation of duties irrespective of whether there have been any imports of the product under consideration during the review investigation period or not. However, it was examined whether other parameters listed under the AD Rules could have contributed to injury to the domestic industry. It is noted as follows:

Volume and Prices from Other Countries

74. It is noted from the import statistics that the subject goods have been imported from a number of other countries and their volumes are above the *de minimis* limits. Imports of the subject goods from China PR, Japan, Korea RP, Malaysia, Russia, Taiwan and Thailand are significant in volume and have cumulatively shown increase over the injury period. It was, therefore, examined whether imports from these sources would have caused injury to the domestic industry. It is noted that the domestic industry has already filed an application alleging dumping of the subject goods from these sources and after due examination thereof, the Authority has initiated anti-dumping investigations vide notification dated 3rd November 2009, in order to examine whether apparent dumped imports of the subject goods from these countries have caused injury to the domestic industry. Since imports from these countries are apparently at dumped prices; the Authority holds that injury from such apparent dumped imports is not required to be segregated for the present case. The imports from other sources are *de minimis* in volumes and therefore, could not have caused injury to the domestic industry.

Contraction in Demand and / or Change in Pattern of Consumption

75. It is noted that the demand of the subject goods has increased by 35.78% in the period of investigation as compared to the base year. There is also no indication of any change in the consumption pattern.

Trade Restrictive Practices of and Competition between the Foreign and Domestic producers

76. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. The domestic producers compete amongst one another and at the same time compete with the landed prices of the subject goods. The price of the domestic industry is influenced substantially by the landed price of subject goods. Moreover, no evidence has been submitted by any interested party even to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

Development of Technology

77. No party has raised any issue with regard to developments in technology as being the cause of injury to the Domestic Industry. Nor there appears to be any significant development in technology that the same could be the principal cause of injury to the domestic industry.

Export Performance

78. There are no exports of the subject goods. In any case, the Authority has considered profitability and other price parameters only in respect of domestic operations.

Productivity

79. It is noted that the productivity of the domestic industry has shown decline. While the domestic industry has argued that the decline in productivity was due to the decline in production triggered by dumping and such injury was not required to be segregated, the Authority has examined whether the information relating to domestic industry would have shown injury, had productivity of the domestic industry been the same. It was noted that the impact of lower productivity is on cost of production and consequently profit/loss, return on investment and cash flow. The Authority has estimated the levels of profits, ROI and cash flow considering there was no decline in productivity and found that the condition of the domestic industry would not have been significantly different.

80. The Authority thus concludes that other listed known factors have not caused injury to the domestic industry.

81. Thus, the Authority holds that the performance of the domestic industry over the injury period has deteriorated due to dumped imports from subject territory. This is established by the following:

- Imports of the product under consideration have increased significantly. As a direct consequence thereof, the domestic industry has lost its market share.
- The domestic industry has lost sales volumes due to the presence of the dumped imported subject goods in India at prices lower than their cost of production.
- The market share of the imports increased significantly and as a direct consequence thereof, the market share of the Indian producers has declined.
- The decline in sales volumes appears to be a direct consequence of dumped imports from subject territory;
- The imports are undercutting the prices of the domestic industry.

- f) The imports are suppressing the domestic prices. The domestic industry has been prevented from increasing its prices in line with the increase in its cost of production due to availability of low priced imported goods.
- g) The deterioration in profits, return on capital employed and cash profits are apparently as a result of the dumped imports;
- h) The imports are still continuing at dumped prices and the extent of dumped imports has remained at significant levels. Apparently, the circumstances, which were prevalent at the time of original investigations, are very much in existence even till date. There has been no change in the circumstances, which only reflects that the dumping would continue, may be at higher levels, if the duties are allowed to expire.
- i) Growth of the domestic industry has become negative in respect of a number of parameters.

82. Thus, the Authority concludes that the dumped imports originating in or exported from the subject territory have caused material injury to the domestic industry within the meaning of Rule 11 read along with Annexure II of the AD Rules.

M. Likelihood of recurrence of dumping and injury

83. The Authority notes that dumping is continuing from subject territory in spite of the antidumping duty in force and the domestic industry continues to suffer material injury due to such dumped imports. Further, dumping of the subject goods from the subject territory and consequent injury to the domestic industry is likely to continue, if the anti-dumping duties in force cease to operate. Therefore, further examination of the likelihood of recurrence of dumping and injury is not required.

N. CONCLUSIONS

84. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the state of continuation of dumping and consequent injury and likelihood of continuation of dumping and injury, the Authority concludes that:

- i. The subject goods are entering the Indian market at dumped prices and dumping margin of the subject goods imported from subject territory is significant and above the de-minimis limits prescribed. The subject goods continue to be exported to India at dumped prices inspite of existing anti dumping duties.
- ii. The situation of domestic industry has deteriorated further in spite of the existing anti dumping duties. Further, should the present anti dumping duties be revoked, injury to the domestic industry is likely to continue and intensify.
- iii. The deterioration in the performance of the domestic industry is because of dumped imports from the subject territory.
- iv. The current level of anti dumping duty is insufficient to address the continued dumping and consequent injury to the domestic industry and thus the anti-dumping duty is required to be extended and modified.

O. RECOMMENDATIONS

85. Having concluded that the product continues to be exported at dumped prices, the current dumping margin and injury margin establishes the need for revision in the anti-dumping duty in force, the situation of the domestic industry continues to be vulnerable and there is likelihood of continuation of dumping and consequent injury on account of imports from subject territory, if the duties are revoked. Thus, the Authority is of the opinion that the measure is required to be extended and the quantum of Anti-dumping duty is required to be modified in respect of imports from subject territory as specified in the duty table below.

86. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, antidumping duty as per amount specified in Col 8 of the table below is recommended to be imposed in the event of acceptance of these recommendations by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject territory.

Duty Table

Sl. No	Heading/ Sub- heading	Description of goods	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	39042210	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	European Union	Any	Any	Any	267.38	Per MT	US\$
2	39042210	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Any	European Union	Any	Any	267.38	Per MT	US\$

87. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

88. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

P. K. CHAUDHERY, Designated Authority